an>

Title: Combined discussion on the Budget and Demands for Grants Nos. 1 to 13 in respect of Budget for the National Capital Territory of Delhi for 2014-15 (Discussion concluded).

HON. SPEAKER: Now, the NCT of Delhi Budget. Item Nos. 11 and 12 shall be taken up together.

Motion moved:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third Column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of the payment during the year ending on the 31st day of March, 2015, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 1 to 13."

Now, Shri Deepender Singh Hooda.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदया, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और उसके बजट पर आज यह चर्चा है। इस चर्चा की पृष्ठभूमि क्या है। एक बहुत बड़ी जीत दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को इस लोक सभा चुनाव में मिली। लोगों को बहुत आशाएं और आकांक्षाएं थीं और केवल दिल्ली में ही नहीं, जो दिल्ली का एनसीआर क्षेत्र है, जिसमें 19 लोक सभा क्षेत्र है, उनमें से 18 भारतीय जनता पार्टी की झोली में लोगों ने बहुत आशाओं और उम्मीदों के साथ डाले हैं कि ऐसा बजट दिल्ली में आयेगा कि दिल्ली बहुत तेजी से विकास की तरफ आगे जायेगी। वे आशाएं और बढ़ जाती हैं, क्योंकि आदरणीय अरुण जेटली भारत के वित्त मंत्री हैं, उन्हें दिल्ली का बजट प्रस्तुत करने का मौका मिला है और दिल्ली से उनका जुड़ाव है। वह दिल्ली छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, मैं भी दिल्ली की छात्र राजनीति में हिस्सेदारी लेता रहा हूं। उस बात को सोचकर बजट और भी अच्छा होने की हमें आशा थी। मगर मैं मानता हूं, जितनी उम्मीदें थीं, जितनी आशाएं थीं, उसके अनुरूप यह बजट नहीं आया। मैं एक-एक करके अपनी बात इस चर्चा के माध्यम से रखूंगा। यदि हम इससे पहले पिछले आठ महीनों की बात करें, दिल्ली में जिस तरीके से एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को इस लोक सभा चुनाव में मिली, सात-आठ महीने पहले दिल्ली में उसी तरीके की बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को मिली थी। फिर क्या कारण रहा कि छः-सात महीनों में ही लोगों की भावना बदली। हमने इतनी तेजी से भावना बदलते नहीं देखा। वह सरकार भी बड़ी आशाओं के साथ बनी थी, ठीक उसी प्रकार बनी थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने साथ दिया, उनका भी लोगों ने साथ दिया था। देश के नौजवानों और अन्य बहुत से लोगों को उम्मीद जगी थी कि यह एक नई पार्टी आई है, इसकी नीयत ठीक है। मैंने भी खुले मंचों से इस पार्टी के बारे में बोला। श्री भगवंत मान जी यहां बैठे हैं, * के साथ खुले मंचों पर चर्चा हुई और मैंने भी खुले मंचों से कहा कि हमें आपकी नीयत पर शक नहीं है, मगर आप जो रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, वह शायद ठीक नहीं है। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने उन्हें मौका दिया और जो लोग आम आदमी की बात करते थे, वही लोग आम आदमी से भागते हुए दिखाई दिये। उन्होंने भी बड़ी-बड़ी आशाएं जगाई थीं, जैसे बीजेपी ने जगाई। आम आदमी जब उन लोगों से मिलने आए, वे लोग सैक्रेटेरिएट पर पहुंचे तो एक विचित्र दृश्य देश को देखने को मिला। मैं समझता हूं कि ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। मैंने क्या दृश्य देखा कि लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने-अपने काम बता रहे थे और दिल्ली के मुख्य मंत्री सैक्रेटेरिएट की छत पर खड़े होकर लोगों को कह रहे थे कि वह आज नहीं मिलेंगे, आज बात नहीं करेंगे। लोगों के बीच में रहने से उनकी बातें सुनने से यह देश चला करता है, सरकारें चला करती हैं। मैं समझता हूं कि लोगों से भागने से समस्याओं के हल नहीं हुआ करते। उसके बाद उनके सभी मंत्रियों के बीच एक होड़ लग गई कि किस तरीके से आज खबरों में रहें। हर रोज अलग-अलग मुद्दों पर कुछ न कुछ बोलते रहे और उसी होड़ में आगे बढ़ते-बढ़ते वह आम आदमी से और दिल्ली से सरकार छोड़कर भाग गये और लोगों ने उन्हें उसकी सजा दी, चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी की सरकार बनी।

महोदया, अब मैं बजट पर आता हूं। एक बड़ा मुद्दा बिजली का था।

माननीय अध्यक्ष : आपने जो नाम लिया है, वह रिकार्ड पर नहीं जायेगा, क्योंकि वह यहां के सदस्य नहीं हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : इस बजट में एक बड़ा मुद्दा बिजली का था। इस बजट में मुख्य बिन्दु बिजली था, क्योंकि पिछले दो वर्षों से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का घनघोर विरोध हुआ, किस बात को लेकर विरोध हुआ कि दिल्ली में जो बिजली के रेट है, वह कांग्रेस पार्टी ने बिजली की कंपनियों के साथ सांठ-गांठ करके तय किये हैं। बिजली के रेट ज्यादा है, हम आते ही कम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कितना कम करेंगे, पचास प्रतिशत कम करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लोगों ने उन्हें उस बात की सजा दी। बीजेपी ने कहा कि हम तीस प्रतिशत कम करेंगे, उन्होंने कहा कि हम आते के साथ ही, सरकार बनते ही तीस प्रतिशत कम करेंगे। श्री हर्षवर्धन जी यहां बैठे हैं, इन्होंने दिल्ली विधान सभा में कहा कि सरकार बनते ही हम तीस प्रतिशत बिजली के दाम घटायेंगे। इसे चुनाव का मुद्दा बनाया। दो वर्ष तक संघर्ष किया गया और उसके बाद इनके हाथ में तिजोरी की चाबी आई, बजट पेश हुआ। लेकिन क्या हुआ? डीईआरसी ने पैस कॉंपेंसेशन कर के कहा कि हम फ्यूल सरचार्ज बढ़ा रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं। उसके बाद सब्सिडी की बात ले कर आए। वित्त मंत्री जी ने 260 करोड़ रूपये की सब्सिडी दी। यह वही सब्सिडी है, जिसका आप लोगों ने विरोध किया था। कांग्रेस के समय में 200 यूनिट तक 2 रूपये की सब्सिडी थी, 400 यूनिट तक 1 रूपये 20 पैसे की सब्सिडी थी। जो 200 करोड़ रूपये की सब्सिडी कांग्रेस के समय मिलती थी, वही आज आपने 260 करोड़ रूपये की सब्सिडी दी है। तब आपने यह कह कर सब्सिडी का विरोध किया था कि सब्सिडी का मतलब एक जेब से पैसा निकाल कर दूसरी जेब में देना है। हम बिजली कंपनियों से 30 प्रतिशत दाम कम करायेंगे। आज दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि वह वादा आपने कैसे किया था? अगर सब्सिडी देनी थी तो कांग्रेस वाली सब्सिडी ज्यों की त्यों लागू करनी थी। हर्षवर्धन जी ने दिल्ली विधान सभा में जो बात कही थी, मैं वह बात रखना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी, हर्षवर्धन जी ने विधान सभा में यह बात रखी थी, मैं दिल्ली विधान सभा की 2 जनवरी, 2014 की प्रोसिडिंग कोट कर रहा हूं - अगर वास्तव में दिल्ली के लोगों की सहायता करना चाहते थे तो डीईआरसी को बुलाते, बुला कर बिजली कंपनियों के ऊपर दबाव डालते, कम करिए 50 प्रतिशत बिल, नहीं तो बाहर का रास्ता जाइए। हमारी सरकार बनते ही हम 30 प्रतिशत बिजली कम करेंगे। कहां आपने 30 प्रतिशत कम किया है? यह आपने नहीं किया है। मेरी जेब का पैसा निकाल कर, मैंने जो पैसा टैक्स के रूप में दिया है, वह पैसा मेरे स्कूल बनाने के लिए था, मेरे अस्पताल बनाने के लिए था, मेरे डिस्पैंसरी बनाने के लिए था, वह मेरे हितों की रक्षा करने के लिए, गरीब साथियों की मदद करने के लिए था। आप मेरे ही पैसों में से दो सौ-ढाई सौ करोड़ रूपये निकाल कर, सब्सिडी के रूप में बिजली कंपनियों को दे रहे हैं। आप बिजली कंपनियों को ओब्लाइज कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी जनवरी में दिल्ली विधान सभा में दो सौ-ढाई सौ रूपये की बात कर रहे थे। आपने तो 260 करोड़ रूपये की सब्सिडी दी है। आपने आपस में बात नहीं की है। मुझे लगता है कि आपको हर्षवर्धन जी से चर्चा कर के और उन्हें कॉंन्फिडेंस में ले कर यह बजट बनाना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने बिजली के भाव कम करने के लिए योजना बनाई है। उसके बारे में हमने बताया था कि किस प्रकार से रेट कम करेंगे। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम बिजली के रेट 30 प्रतिशत कम करेंगे। बड़े-बड़े पोस्टर लगे कि बिजली के रेट 30 प्रतिशत कम होंगे। मैं समझता हूँ कि जैसे कई स्टोर्स की बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स लगती हैं कि 50 प्रतिशत सेल, लेकिन नीचे छोटा सा लिखा जाता है कि केवल सितेक्ट आइटम्स पर है। उसी प्रकार से यह लिखा था कि बिजली के रेट 30 प्रतिशत कम करेंगे। मगर जो रेट था, वह बिल्कुल छोटा-छोटा लगाया हुआ था क्योंकि दिल्ली में बिजली 30 प्रतिशत कम हो गई थी। छः और आठ घंटे का कट, इस गर्मी के अंदर दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ा है। आपने बिजली के रेट कम नहीं किए हैं, बल्कि आपने दिल्ली में 30 प्रतिशत बिजली ही कम कर दी। लोग पूछ रहे हैं, लोग फैसला करेंगे कि 15 वर्ष तक विकास, सुख और शांति के साथ जो दिल्ली आगे बढ़ी है, वह समय ठीक था या यह आठ महीने की अराजकता, आठ महीने बिजली के भाव बढ़ना, आठ महीने की बिजली में कटौती ठीक है। ये दिल्ली के लोगों का भविष्य बनाने का काम करेंगे।

आज लोग सवाल पूछ रहे हैं। स्कूल पर सवाल पूछ रहे हैं। आदरणीय वित्त मंत्री की बुद्धिमत्ता के हम सब प्रशंसक हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि कि दिल्ली में आज 500 नए स्कूलों की आवश्यकता है। दिल्ली में हर वर्ष एक लाख बच्चों की एनरोलमेंट बढ़ रही है। पिछले बजट में, जो कांग्रेस की सरकार ने पेश किया था, उसमें सौ नए स्कूलों के बनने की व्यवस्था की गई थी। उसको घटा कर आपने अपने बजट में कहा है कि हम कि हम 20 नए स्कूल बनाएंगे। जो एक लाख बच्चे हर वर्ष दिल्ली के स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए केवल 20 नए स्कूल? आपने खुद कहा कि 500 स्कूलों की आवश्यकता है और उसके बाद आपने कहा हम 20 नए स्कूल बनाएंगे। यानि कि 25 साल तक इस देश के लोगों को अच्छे दिन की बाट देखनी पड़ेगी। अच्छे दिन का इंतजार 25 वर्ष तक करना पड़ेगा। यह कहां का न्याय है? आपने कटौती क्यों की? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 100 स्कूलों की घोषण की थी, जिनमें 40 स्कूलों के लिए भूमि अधिग्रहण भी की जा चुकी है। उन पर कार्रवाई जारी है। उनको कट कर के आपने केवल 20 स्कूलों की घोषणा की है। उसके बाद आपने ट्रांस्पोर्ट को ले कर घोषणा की है। आपने कहा है कि हम आधुनिक सुविधाओं से लैस 1300 नई बसें दिल्ली में चलाएंगे।

13.00 hrs.

मगर आजकल कम्प्यूटर के जमाने में कट, कॉपी, पेस्ट का एक प्रचलन चला है। यही पिछले साल कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 1300 नयी बसें चलायेंगे। उस समय बीजेपी ने इसका विरोध किया था, लेकिन आपने पिछले साल के बजट से यूं का यूं वही पन्ना उठाकर अपने बजट में जोड़ लिया है।

महोदया, मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इन 1300 बसों का कांग्रेस पार्टी ने प्रावधान किया था, कार्यवाही की थी, पूरी प्लानिंग की थी और केवल टेंडर अलॉट करना बाकी है। आपने बजट में कहा कि हम 1300 नयी बसों का प्रावधान करेंगे, कम से कम अगर आपको करना था तो 1310 की घोषणा कर देते, 1400 की घोषणा कर देते, मगर यूं का यूं ही कट, कॉपी, पेस्ट कर दिया। मैं समझता हूं कि आज के दिन कट, कॉपी, पेस्ट का जमाना है।

महोदया, उसके बाद मेट्रो की बात आयी, मोनो रेल की बात आयी, हमने प्रावधान किया था, इस दिल्ली में हमारी पार्टी ने मेट्रो बनाने का काम किया था। जब हम मेट्रो का प्रस्ताव लेकर आये थे, जब हम मेट्रो बना रहे थे तब बहुत से हमारे दल, जो आज यहां बैठे हैं, उन्होंने उसका विरोध किया था कि मेट्रो आयेगी तो दिल्ली के अन्दर रिक्शा वालों का नुकसान होगा, ऑटो वालों का नुकसान होगा। आज मेट्रो का जाल पूरी दिल्ली में बिछा है। हमने अपने पिछले बजट में यह भी कहा था कि हम मोनो रेल भी इस दिल्ली में लेकर आयेंगे, जिस तरह से दुनिया की बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानियों में मोनो रेल है। पहली मोनो रेल का रूट हमने गांधी नगर से लेकर मयूर विहार तक प्रस्तावित किया था कि गांधी नगर से मयूर विहार मोनो रेल का पहला रूट बनेगा। जिसके लिए हमने उसमें पूरा आबंटन भी किया था, लेकिन इस बजट में उसका कोई जिक्र नहीं है। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी बतायेंगे कि इस बजट में उसका जिक्र क्यों नहीं है?

राजनाथ सिंह जी, अभी यहां बैठे थे, वे बवाना गये थे और उन्होंने बवाना जाते ही कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हमारा पहला काम होगा कि हम बिजली का बिल 30 प्रतिशत कम करेंगे और दूसरा हमारा काम होगा कि हम लाल डोरा बढ़ाने का काम करेंगे। दिल्ली देहात में लाल डोरे का मुद्दा बहुत बड़ा है। दिल्ली देहात के लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ गया वह वादा? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लाल डोरा बढ़ाने के लिए कार्यवाही शुरू की थी, उस कार्यवाही के लिए कोई आबंटन इस बजट में नहीं किया गया है। दिल्ली देहात के लोग इस बारे में पूछ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है कि जो दिल्ली देहात के किसान का खेत है, उस खेत में बिजली का चार्ज 2 रूपये 70 पैसे है और उससे अगला खेत, जो उसके पड़ोसी का खेत है, जो खेत हरियाणा में है, उस किसान का बिजली का चार्ज 10 पैसे है। वहां 10 पैसे है और यहां 2 रूपये 70 पैसे है। क्या कारण है कि पेट्रोल का जो भाव है, पेट्रोल दिल्ली में 2 रूपये ज्यादा महंगा है, हरियाणा में पेट्रोल 2 रूपये सस्ता है। डीजल का जो भाव है, डीजल हरियाणा में 2 रूपये सस्ता है और दिल्ली में डीजल 2 रूपये महंगा है। दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि हम 2 रूपये ज्यादा क्यों दे रहे हैं? हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, क्या यह हमारी गलती है? हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया है। आज दिल्ली के लोग इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं। इन सवालों का जवाब आदरणीय वित्त मंत्री जी अपने जवाब में देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है।

अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा है। आपने खुद अपने बजट में स्वीकार किया है कि ऐसी 1600 कॉलोनीज हैं। तकरीबन 840 कॉलोनीज हमारी सरकार ने रेग्युलराइज्ड की थीं, आपने उन कॉलोनीज के लिए क्या प्रावधान किया? चालीस लाख लोग उन कॉलोनीज में बसते हैं। दिल्ली के सभी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी सवाल पूछिए, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। उन कॉलोनीज में से केवल पचास कॉलोनीज के लिए पीने के पानी का प्रावधान किया है। जिस तरीके से पच्चीस साल में आपने स्कूलों का प्रबन्ध करने का आबंटन किया है कि पच्चीस साल में आबंटन होगा, उसी प्रकार से इन कॉलोनीज के लिए इस रेट से बत्तीस साल लग जाएंगे। हमारी राजधानी दिल्ली के अंदर जो चालीस लाख लोग उन कॉलोनीज में रहते हैं, उनके लिए पीने के पानी का प्रावधान करते-करते इस रेट से बत्तीस साल लग जाएंगे। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या हमने आपको वोट इसीलिए दिया था।...(व्यवधान) निशिकान्त जी, आप दिल्ली से नहीं है।...(व्यवधान) आप अपनी बात अपने तक रखिए। ...(व्यवधान) एक और सवाल बनता है।...(व्यवधान)

महोदया, मैं अब निष्कर्ष की तरफ आता हूं।...(व्यवधान) इसी प्रकार एक अन्नश्री योजना हमारी सरकार ने बनायी थी। दो लाख अस्सी हजार जो ऐसे माइग्रेंट लोग दिल्ली के अंदर हैं, जो बीपीएल के अंदर नहीं आ रहे थे, मगर फूड सिक्योरिटी का हम उन्हें फायदा पहुंचायना चाहते थे। ऐसे दो लाख अस्सी हजार माइग्रेंट लोगों के परिवारों में जो महिलायें हैं, जो हेड ऑफ फैमिली हैं, उनको प्रति माह छः सौ रूपए की एक सहायता का प्रावधान ताकि वे अपना बजट सुधार सकें क्योंकि वे फूड सिक्योरिटी के ऐम्बिट में नहीं आ रहे थे, तो वे अपने घर का बजट थोड़ा सुधार सकें।...(व्यवधान) जो दो लाख अस्सी हजार माइग्रेंट हैं, इनमें निशिकान्त जी के संसदीय क्षेत्र से भी शायद बहुत से लोग यहां पर हों।...(व्यवधान) उनके लिए कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है। वह 600 रुपये बंद हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अन्नश्री योजना जो कांग्रेस पार्टी ने चलाई थी, जो गरीब माइग्रैन्ट दिल्ली में रहते हैं उनके लिए चलाई थी जिसमें उनको 600 रुपये प्रति माह दिया जा रहा था, पिछले तीन महीने से 600 रुपये उनको नहीं दिये जा रहे हैं, वह योजना बंद पड़ी है और उसका कोई आबंटन भी इस बजट में नहीं किया गया है। यह गरीब आदमियों की बात मैं रख रहा हूँ। एन.सी.आर. में उनके 18 सांसद हैं और एक सांसद हम भी हैं। हमारी बात पूरी तरीके से सुनी जाएगी। ...(व्यवधान) फिर रेल की बात आई।

माननीय अध्यक्ष : आप बीच में टोकिये मत। आप कनक्लूड कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैं निष्कर्ष पर आ रहा हूँ। महानगरों में रेल में बहुत से दैनिक यात्री होते हैं। रेल बजट में रेल का किराया बढ़ा। रेल का किराया जैसे ही बढ़ा, महाराष्ट्र के सांसद गए, मुम्बई के आस-पास के सांसद गए। उनकी बात सुनकर हमारे रेल मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि 80 किलोमीटर के आस-पास का जो एरिया है, उसमें दैनिक यात्रियों के लिए किराये में जो बढ़ोतरी हुई है, हम उसे तुरंत वापस लेते हैं। क्यों वापस लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर चुनाव हैं। अरे, दिल्ली में भी चुनाव हैं। अगर मुम्बई महाराष्ट्र की राजधानी है तो दिल्ली भारत राष्ट्र की राजधानी है। अगर आपने मुम्बई के 80 किलोमीटर के आस-पास का किराया वापस ले लिया तो दिल्ली के आस-पास का किराया भी आप वापस ले लीजिए, ऐसा आग्रह मैं करना चाहता हूँ। आप चुनावों के नाम पर ही वापस ले लीजिए। महाराष्ट्र में चुनाव हैं, तो दिल्ली में भी चुनाव हैं।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, हो गया।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : महोदया, आप बार-बार आग्रह कर रही हैं और मैं आपके आग्रह को नहीं टाल सकता। बहुत सी बातें हैं और दिल्ली के लोगों ने बहुत आशाओं के साथ सरकार को बनाया है। मैं उम्मीद करूँगा कि रेल मंत्री जी अपने जवाब में इस बजट में संशोधन करेंगे ताकि कुछ आशाओं पर खरा उतर सकें।

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Madam, the scheme of 'within 80 kilometres' is applicable not only in Maharashtra but also across the country.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: Would it be done in Delhi also? मैडम, अगर दिल्ली में यह हो जाता है तो मैं आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करूँगा। इस 80 किलोमीटर में रोहतक भी आ जाएगा।

अंत में, मैं अपने क्षेत्र की एक मांग रखना चाहता हूँ जिसके लिए सरकार आबंटन करे। हमारी दिल्ली की सरकार ने प्रस्तावित किया था कि एक फ्री एक्सप्रैसवे बहादुरगढ़ से लेकर रिंग रोड तक 14 किलोमीटर का बनाया जाए जो, जिसकी 1500 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मैं समझता हूँ कि हम जो आमने-सामने बैठे हैं, इनको जोड़ने का काम भी हमें करना है, इसी प्रकार से हरियाणा-दिल्ली को जोड़ने का काम भी हमें करना है। उस एक्सप्रैसवे के लिए भी कोई आबंटन नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके लिए भी आबंटन करेंगे और लोगों की आशाओं का ध्यान करेंगे नहीं तो इनका वही हश्र होगा जो आम आदमी पार्टी का हश्र हुआ था। ...(व्यवधान) दिल्ली के चुनावों में आपने जो बिजली के बिल में 30 प्रतिशत की कटौती का वायदा किया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि वे 30 प्रतिशत बिजली के बिल ...(व्यवधान) हर्षवर्धन जी हँस रहे हैं, बैठ-बैठे मंद-मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हर्षवर्धन जी को पता है कि अगर इनकी बात अरुण जेटली जी ने मान ली होती तो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की यह हालत नहीं होती। मैं जेटली जी से कहूँगा कि वे हर्षवर्धन जी से भी बात कर लें। ...(व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वित्त मंत्री जी उन सारी बातों को पूरा करेंगे जो हमने यहाँ रखी हैं और लोगों के हित में दिल्ली के बजट में संशोधन करने का काम करेंगे।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 14.10 hours

13.09 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Ten Minutes

past Fourteen of the Clock.

HON. CHAIRPERSON : We will continue with the general discussion on the National Capital Territory of Delhi Budget and Demands for Grants in respect of the Budget for Delhi.

Now, Shrimati Meenakshi Lekhi.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे दिल्ली के बजट पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, जब कांग्रेस के सांसद हुड्डा जी बोल रहे थे तो मुझे लगातार महसूस हो रहा था कि वह शायद इस तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि अपने हर वक्तव्य के बाद वह कह रहे थे कि दिल्ली में डिज़ल की कीमत यह है, लेकिन हरियाणा में नहीं है। यानी शीला दीक्षित सरकार ने जनता को मंहगा डिज़ल दिया, लेकिन हरियाणा की सरकार ने नहीं दिया। दिल्ली की सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाए, हरियाणा की सरकार ने नहीं बढ़ाए। मुझे लगा कि वह विपक्ष से नहीं पक्ष से हैं और उनकी सरकार ने दिल्ली की जनता को लगातार तूस्त रखा है। जिसकी वजह से आज नज़ारिया यह है और नज़ारा यह है कि आज दिल्ली के बजट पर बोलने के लिए हरियाणा से सांसद भी उधार में आए हैं।

महोदय, दिल्ली भारत की राजधानी है और यहां पूरे देश से लोग आते हैं। इसी में नई दिल्ली क्षेत्र आता है, जहां हम सब इस समय बैठे हैं। इस दिल्ली की कुछ परम्पराएं हैं। मुझे एक शेर इस मौके पर याद आ रहा है-

'कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर-ए-ज़मॉं हमारा'

ऐसी घोटालेबाज सरकार और एक ऐसी सरकार जो अपनी जिम्मेदारियों से भागती रही, उसके बाद आज दिल्ली को राष्ट्रपति शासन मिला है। उस राष्ट्रपति शासन द्वारा और केन्द्र में हमारी सरकार होने के बाद, जिसे दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार दिया और हमारे हाथों को मजबूत किया एवं एक बेहतरीन बजट दिल्ली को प्राप्त हुआ है। मैं माननीय वित मंत्री जी को दिल्ली के बजट के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। इस बजट में हमारी जो सोच है 'Minimum Government Maximum Governance' वह स्पष्ट रूप से दिखायी देता है। मैंने अपना चुनाव पंचवर्षीय पंचनामे से शुरू किया था, जिसमें कहा था कि पांच मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। पहला, जहां भय वहां सुरक्षा। दूसरा, जहां अंधकार वहां रोशनी। तीसरा, जहां प्यास वहां स्वच्छ पानी। चौथा, जहां झुग्गी वहां मकान और पांचवा, जहां गरीबी वहां रोज़गार मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली के बजट में इन पांचों विषयों पर बहुत अच्छे तरीके से एक-एक विषय पर बेहतरीन प्रस्तुति की गयी है और दिल्ली की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। जहां पर सेफ्टी, सिक्यूरिटी और सुरक्षा का विषय आता है तो दिल्ली में अपराधों की संख्या लगातार बढ़ी। खासतौर से, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में बढ़ोतरी हुई और जून के महीने तक 70,000 रेप केसेज और तमाम अपराध हुए जो पिछले वर्ष 80,000 थे। उसके कई कारण हैं। उसमें से एक कारण बेहतरीन रिपोर्टिंग भी है। ऐसे में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय था और माननीय वित मंत्री जी ने, जिसे कहा जाए वन स्टॉप क्राइसिस सेन्टर, उनके लिए पैसों का प्रावधान अपने बजट में किया और उसके आधार पर महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े हुए रिहैबिलिटेशन मैनेजमेंट जैसे तमाम विषयों के ऊपर काम करने के लिए बजट में प्रावधान किया है। साथ ही, वूमेन हेल्पलाइन, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और अन्य कई स्कीमों का प्रावधान भी किया। मैं माननीय वित मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि दिल्ली के स्कूल कर्रीकुलम के अन्दर, खासतौर से गर्ल्स स्कूलों और गर्ल्स कॉलेजों में, जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है, उसे आवश्यक करने का भी प्रावधान करें। उस से महिलाओं की सुरक्षा को एक शक्ति प्रदान होगी।

दूसरा विषय बिजली का है। हमारा नारा "जहां अंधकार, वहां रोशनी " है। ऐसे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चरमराहट है, वह इस गर्मी में पूरे दिल्लीवासियों को भुगतनी पड़ी। उसके लिए पूर्व में जो दिल्ली की सरकार रही, पंद्रह सालों से हुडा जी की ही पार्टी की सरकार रही, वह जिम्मेदार है। उसके बाद जो सरकार आयी उसने अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से नहीं निभायी और जिसके रहते इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो पैसा खर्च होना था, वह पैसा खर्च नहीं हुआ। ऐसे में मैं वित मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 260 करोड़ रुपये का प्रावधान किया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की। ग्रिड के अंदर बिजली कम है, ऐसा नहीं है, बल्कि उस बिजली को ट्रांसमिट करने के लिए जो सब स्टेशन और तारों के लिए जो लाइन-1, लाइन-2, और लाइन-3 का प्रावधान होना चाहिए, उस पर पिछली सरकारों ने कुछ काम नहीं किया था।

महोदय, इस इलाके से सांसद होने के नाते मैं एनडीएमसी काउंसिल की मेम्बर हूं और प्रिज़ाइडिंग ऑफीसर भी हूं। इसलिए, मैं संसद के पटल पर एक और विषय रखना चाहती हूं जो सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अगर हम सौर ऊर्जा को यूनियन बजट से जोड़कर और जो दिल्ली का बजट है, उस से मिला कर देखें तो उस पर विशेष काम किया गया है। एनडीएमसी सौर ऊर्जा के माध्यम से एक मेगावाट बिजली तुरंत बनाने जा रहा है। एनडीएमसी की जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी छतों का हम सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसे में जो पहले प्रावधान होता था कि सरकार सब्सिडी देती थी और खरीददार को कहा जाता था कि यह आपकी सब्सिडी है, लेकिन आपको इतना पैसा लगाना पड़ेगा, उस से बचने के लिए एग्रीगेटर है, वह अपना पैसा खर्च करेगा और जो जगह है, उसका इस्तेमाल करने के लिए किराया भी देगा। उस से बनने वाली सौर ऊर्जा ग्रिड में जाएगी जो बाकी जनता के इस्तेमाल में आएगी। इस प्रकार से "ग्रीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली " का जो नारा है, वह मात्र नारा न रहे बल्कि दिल्ली को वाक़ई हरा-भरा और एक इफिशिएंट सिटी बनाने का काम कर सके। इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया, मुझे इस बात की भी विशेष रूप से खुशी है।

महोदय, माननीय हुडा जी ने बिजली से संबंधित कुछ प्रश्न उठाए और कहा कि आपने 30 प्रतिशत का वायदा किया था और आप अपने वायदे पर खरे नहीं उतरे तो मैं गणित की एक बड़ी सिम्पल-सी कैलकुलेशन बताने वाली हूं।...(व्यवधान) लोगों तक संसद के माध्यम से यह पहुंचेगी। जो ज़ीरो से 200 यूनिट है, उसके ऊपर हमारी सरकार ने एक रुपये 80 पैसे की सब्सिडी देना तय किया है। एक रुपए 80 पैसे की सब्सिडी देना। जिस प्रति यूनिट की कीमत चार रुपए है, उसमें से जब एक रुपए 80 पैसे कटौती कर लेते हैं तो दो रुपए बीस पैसे उसकी कीमत आती है। उसको जब आप प्रतिशत में केलकुलेट करते हैं तो वह ठीक तीस प्रतिशत आता है और इसमें 50 प्रतिशत के आसपास, 50 प्रतिशत से थोड़े अधिक जो दिल्ली के लोग हैं, वे कवर होते हैं। इसके ऊपर जो दो सौ से चार सौ वाला यूनिट है, इस यूनिट के अंदर सब्सिडी 80 पैसे की है।...(व्यवधान) आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर बोलें। ...(व्यवधान) आप तो भाग गए थे, जो जिम्मेदारी से भागे हुए लोग हैं, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। ...(व्यवधान) जो जिम्मेदारी से भागने वाले लोग हैं, उनको बोलने का अधिकार नहीं है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please address the Chair.

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Keep quiet now.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : जो दूसरा यूनिट 201 से चार सौ वाला है, उसकी कीमत पांच रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट है। उस पर जब हम 80 पैसे की छूट देते हैं, सब्सिडी देते हैं, तो उसमें भी तकरीबन 13.5 प्रतिशत का लाभ मिलता है। इन दोनों केलकुलेशन को जब आप जोड़ते हैं तो 84 प्रतिशत दिल्ली की जो जनता है, वह इससे कवर होती है। इसके बाद जो विषय आया,...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please try to conclude.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : सर, मैं आग्रह करूंगी कि मुझे थोड़ा सा अधिक ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The time allotted to BJP is one hour and two minutes. There are seven speakers. So, unless you speak within that time, it will be difficult.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : Sir, allow me to ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: What I am telling is that you know that this is the time given. You can find out a way so that your seven speakers can be accommodated.

You just try to conclude.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : Sir, we will take care, but I have to cover all the five points which I have specified and I have to reply to Shri Hooda's points also.

HON. CHAIRPERSON: I leave it to you.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : Please, Your Lordship.

Your Honour, about housing also, जहां झुग्गी, वहां मकान का जो विषय हमने चुनाव से पहले लिया था, उसके लिए भी एफोर्डेबल हाउसिंग जो है, उस पर काम किया जाए। हमारे जो इलाके हैं, वे झुग्गी कलस्टर से फ्री होकर लोगों को बेहतरीन मकान सस्ती कीमतों पर प्राप्त हों। उसके लिए भी काम किया जाए।

माननीय वित्त मंत्री जी ने 185 नये शेल्टर बनाने की जो योजना बताई है, उससे भी हमारे राज्यों को लाभ मिलने वाला है। लेकिन यहां पर मेरा एक सुझाव है कि दिल्ली में 10-15 हजार रुपए प्रतिमाह कमाने वाला व्यक्ति भी गरीब की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसे चार या पांच हजार रुपए महीने का किराया देना पड़ता है। ऐसे में जिस तरीके का एक रिअल एस्टेट माफिया चल रहा है, उसको काबू में करने के लिए हमको सस्ती कीमतों पर घर उपलब्ध कराने पड़ेंगे और जो किराया है, उसको हम उसकी कीमत की तरफ लगवा पाएं तथा सही ढंग से यह योजना लागू हो, इसकी भी मैं अपनी सरकार से अपेक्षा करती हूं। इकोनोमिकली वीकर सैक्शन, खासतौर पर नई दिल्ली इलाके में पिंपलेस पार्क, जोधपुर मैंस और इन इलाकों में जो झुग्गी कलस्टर्स हैं, उनके लिए इस तरीके का प्रावधान किया जाए, पूरी नई दिल्ली के लिए इसका प्रावधान हो। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट अति आवश्यक है, क्योंकि पूर्व में अरबन डेवेलपमेंट मंत्रालय दिल्ली का जो रहा है, कई घोटाले देखे हैं, जिसमें से हाउसिंग स्कीम भी एक घोटाला था। जिस जगह से मैं सांसद हूं और जिन लोगों को हरा कर यहां पहुंची हूं, उनके समय में यह घोटाला हुआ था। जहां प्यास - वहां स्वच्छ पानी। स्वच्छ पानी के दो विषय थे - एक तो ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी और दूसरा शौचालय से, स्वच्छता से जुड़ा हुआ विषय। उसमें भी माननीय वित्त मंत्री जी ने गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेजेस के लिए, खासतौर पर शौचालय के प्रावधान और तमाम दिल्ली में ऐसे शौचालयों के प्रावधान हों। उस पर जो हमें पैसे दिये हैं, उसका प्रावधान किया है, उसके लिए भी मैं शुक्रगुज़ार हूं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह विषय उठाया गया कि दिल्ली में ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो साहब, 45-50 दिन की सरकार से आप उम्मीद करते हैं कि 15 साल की प्यास वह 50 दिन में पूरी कर दे तो यह मुमकिन नहीं है, लेकिन हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। हमारी वाटर ए.टी.एम. से लेकर पीने के पानी को पहुंचाने की तमाम ऐसी योजनाएं हैं, जो कि वित्त मंत्रालय ने घोषित की हैं। यहां पर मैं अपने संसदीय क्षेत्र की ओर से...(व्यवधान)

श्री तारिक अनवर (कटिहार): कारपोरेशन में आप कितने साल से हैं और आप कह रही हैं कि 45 दिन में नहीं हुआ।...(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : साहब, आप बैठिये, मैं बताती हूं।

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

...(*Interruptions*)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : इनकी जो अज्ञानता है, वह साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि, दिल्ली जल बोर्ड शीला जी की सरकार ने दिल्ली सरकार के तहत ले लिया था, वह एम.सी.डी. के तहत नहीं है। इस अज्ञानता के लिए ईश्वर और जनता इनको जवाब दे चुकी है। ऐसे में यह समझने की आवश्यकता है कि दिल्ली जल बोर्ड, जो कि न केवल पानी की व्यवस्था करता है, बल्कि सीवेज की व्यवस्था भी इनके अधिकार क्षेत्र में है और आप पिछले 15 साल से यहां बैठे हुए हो। इसके कारण मैंने गढ़ी गांव में यह देखने के लिए कुछ खुदाई करवाई थी कि पानी में जो सीवेज आ रहा है, उसके कारण क्या हैं। वहां पर मालूम हुआ कि ढाई और तीन फीट के ऊपर सीवेज का पाइप भी डला हुआ है और पीने के पानी का पाइप भी उसी डैप्थ पर डला हुआ है। इसको समझने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा इंजीनियर होने की आवश्यकता नहीं है। एक थोड़े से समझ वाले व्यक्ति को भी यह बात स्पष्ट होगी कि पानी का पाइप धरातल के आसपास होना चाहिए और सीवेज का पाइप कम से कम 8 से 10 फीट की गहराई पर होना चाहिए। दिल्ली में इस तरीके के बहुत से घोटाले हुए हैं, जिसकी वजह से सीवेज का पाइप अपनी गहराई पर न पहुंचाकर ऊपर की तरफ रखा गया और इसीलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में, खास तौर पर नई दिल्ली के क्षेत्रों में, जहां पानी की समस्या है, जहां पर एक ऐसा देश और ऐसी संस्कृति है, जो गरीबों को...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you have taken 15 minutes now. Please conclude now.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI: Much obliged. जहां पर जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, पैदल चलने वाले प्यासे यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था होती थी, उस देश के अन्दर, उस संस्कृति में लोग आज बूंद-बूंद के लिए तरस रहे हों और रोज़ सुबह झगड़े से दिन की शुरूआत होती हो, छोटे-छोटे 4-4, 5-5 साल के बच्चे जरी कैंस लेकर खड़े हों और पानी के 1-1 लीटर, 2-2 लीटर के लिए वहां पर झगड़ा हो रहा हो। यह जो हमें विरासत मिली है, हम उसे कहीं न कहीं सुधारना चाहते हैं, इसलिए उस दिशा में कार्यरत हैं।

उस सुधार में, मैं अपने वित्त मंत्री जी से अपेक्षा रखती हूं कि कुछ जगहें हैं, जैसे आनन्द पर्वत, बलजीत नगर और तमाम जो दो लोक सभा क्षेत्र लगते हैं, जो कि चांदनी चौक और नई दिल्ली का बोर्डर हैं, उसके लिए रिजर्वायर और पम्पिंग स्टेशन का प्रावधान हो। इसी तरीके से कैलाश हिल्स और कैलाश कालोनी के लिए रिजर्वायर और पम्पिंग स्टेशन का प्रावधान हो। ढोंज़ रानी, जहां पर पाइप डले हुए हैं, लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है, उसको भी जोड़ा जाये और पानी की व्यवस्था की जाये। गढ़ी गांव का उदाहरण मैंने आपको दिया, जहां पर सीवेज और पानी मिलकर आ रहा है और बहुत लम्बी ऐसी कतार है, जहां पर पीने का पानी जा भी नहीं रहा, उसका प्रावधान किया जाये। पिलंजी गांव में सीवेज और पानी नहीं है, उनके लिए पाइप्स का प्रावधान हो। आने वाले समय में इन सब विषयों पर मेरी सरकार काम करेगी, इस उम्मीद के साथ मैं यह विषय माननीय वित्त मंत्री जी को बताना चाहती हूं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : जहां गरीबी, वहां रोज़गार, इसको मैं जोड़ना चाहती हूं। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस के जमाने में आया, उसमें दिल्ली में खास तौर पर एक ए.पी.एल. कार्ड है, एक बी.पी.एल. कार्ड है और ऐसे तमाम कार्डों के रहते दिल्ली की जनता को अनाज नहीं मिल पाता। उसके सुधार में जो कम्प्यूटराइज़ेशन का प्रावधान किया है और गाड़ियों के लिए जो जी.पी.एस. सिस्टम का प्रावधान किया गया है, वह लागू किया जाये। वह भी महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन साथ ही साथ इस संसद के पटल पर मैं यह भी रखना चाहती हूं कि कांग्रेस ने अन्नश्री योजना का जिक्र किया, लेकिन वे बताना भूल गये कि अन्नश्री योजना लागू नहीं होती, जब से यह कार्ड सिस्टम दिल्ली में बना, राशन कार्ड्स की वजह से अन्नश्री योजना दिल्ली में लागू नहीं होती। दिल्ली में स्मार्ट कार्ड सिस्टम उपलब्ध हो और फूड सिक्योरिटी का जो मॉडल छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है, वही योजना बनाकर दिल्ली में भी लागू की जाये और उसकी वजह से जनता को लाभ मिल सके। आज हालत यह है कि आपने 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति किया है, इससे पूर्व में 35 किलो अनाज प्रति परिवार मिलता था, अब अगर 20 किलो या 25 किलो अनाज मिलता है तो बाकी अनाज उनको बिना सब्सिडी के बाजार से खरीदना पड़ता है और उन कीमतों पर खरीदना पड़ता है, क्योंकि जो सब्सिडी का लाभ उनको मिलना चाहिए, वह लाभ उनको नहीं मिल पाता है। इस वजह से इस पूरे सिस्टम

को, जिसको फूड सिक्योरिटी एक्ट का नाम दिया गया है, पूरी तरीके से रेशनलाइज करने की आवश्यकता है। मुझे माननीय अटल जी के कुछ विचार याद आ रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट से भी मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now, I have to call the next speaker. You have taken more than 20 minutes.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : Please allow me to speak one last line.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude your speech within one minute.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : मैं अन्तिम बात कहना चाहूंगी। जो देश को बनाना है तो उसके लिए आपको सब्सिडी से हटकर कहीं न कहीं स्किल डेवलपमेंट, रोजगार की योजनाओं पर काम करना होगा। इसी वजह से one says that "if you give a man a fish, you feed him for a day; teach the man to fish, you feed him for a lifetime." It is in this context I want to bring to the notice of this House that India is not a new country and we are not moving towards building a new nation. We are an ancient nation with an ancient value system, and we need to prepare and rejuvenate ourselves so that we can actually face the challenges of the modern world.

*SHRI T. RADHAKRISHNAN (VIRUDHUNAGAR): Hon. Chairman Sir. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu *Puratchithalaivi* Amma has made me a Member of Parliament representing Virudhunagar constituency. I wholeheartedly thank *Puratchithalaivi* Amma for this kind gesture. I thank the voters of my constituency for having reposed faith in me and electing me as their MP. This is the discussion on Delhi Budget. I welcome and support the announcements made in the Delhi Budget. Delhi is at present under Governor's Rule. Delhi State Legislature has unique importance when compared to other States of the country. Delhi is the capital of India. People from all parts of the country come to Delhi frequently. Foreign dignitaries also frequently visit Delhi. Therefore, Union Government should provide special financial package to Delhi. Delhi Assembly is now under suspended animation. Union Government has presented the Budget for Delhi. I urge that such a budget should be passed by the State Assembly being elected by the people of State concerned. Then only the problems and sufferings of the people could be duly addressed. I urge the Union Government to take prompt action in this regard. Price rise should be controlled in Delhi. Drinking water and electricity related issues should soon be solved. Hon. *Puratchiththalaivi* Amma, during the last 3 years of successful rule, has been implementing various welfare schemes in Tamil Nadu. Hon. Amma has presented a tax free budget during the current year. It is the victory for Hon. Amma and the three year term, that people of Tamil Nadu have elected 37 AIADMK MPs to this august House. Hon. Amma has been implementing a welfare scheme of providing 20 kg of rice free of cost to 1 Crore and 85 lakh families every month under Public Distribution Scheme in Tamil Nadu. Mixies, Grinders, laptops, bicycles are provided free of cost. Many states of the country are trying to follow such schemes that are implemented by Hon. Amma in Tamil Nadu. Amma Unvagam- a Canteen facility- is a scheme that is followed in other countries also. Such welfare schemes should be followed in Delhi. This Delhi budget should be passed in Lok Sabha. We fully support this budget. MPs who represented Virudhunagar during previous Lok Sabhas have paid only lip service and done nothing to the development of this constituency. Hon. Amma has been kind enough to sanction Rs.200 crore for setting up ring road in Virudhunagar constituency. I thank Hon. Amma for this kind gesture. I fully support Delhi Budget.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Budget of the Delhi Government which is the National Capital Territory of Delhi. It was presented by the Finance Minister Shri Arun Jaitley. This Budget is presented with an eye on the future Delhi elections which may happen any time considering the state of flux the Delhi is in. Let me start by stating two problems. Mr. Jaitley is a resident of Delhi. He was the President of the Delhi University Students' Union from where he has traveled to become the Finance Minister of the country. He knows the problems of Delhi intimately. But the BJP's hold on Delhi has been tenuous. In the earlier days, BJP used to win all seats from Delhi and then, the BJP also had formed the Government in the National Capital Territory. The BJP lost it when Mrs. Shiela Dikshit became Chief Minister and Mrs. Dikshit was allowed to continue for 15 years sidelining the BJP altogether.

For the first ten years, the Congress Government's performance was good. Bhagidari system was introduced. There were Residents Welfare Associations who use to become participants in the Government. It was the Commonwealth Games which brought bad name to the Congress and its Government. There was corruption not only in holding the Commonwealth Games but the corruption was also in the Delhi Government, as a result, we heard of Road over Bridge collapsing suddenly before the Commonwealth Games. The Congress lost the confidence among the people. The people were still not prepared to trust the BJP. As a result, when the elections were held, an entirely new party, Aam Aadmi Party(AAP), came to power in Delhi. There was a lot of hope in the country that this party is led by a non-politician, who has fought against corruption and he was former IITian and IRS officer. He brought new hope to the people of the country. But the irresponsible way in which the AAP Government resigned has belied the hope of all those who have placed their faith on the Aam Aadmi Party. So, in the Lok Sabha Elections, people backed BJP which has again won all the 7 Lok Sabha seats from Delhi. But there are already murmurs of discontentment. I read in some newspapers that one of the MPs from Delhi is a Bhojpuri actor. He is not to be found by his voters anywhere. We also saw the actions of another Delhi MP, the other day, when he had to apologize in the House. Let the BJP not take it for granted that people have really reposed their faith in them. They lost their faith in the Congress. They thought the AAP as an alternative. But with the AAP's irresponsible behaviour, people were left with no choice and they have gone in for the BJP.

The main question is this. Why I am speaking on this Budget is that I worked in the Urban Development Ministry for some time. I know the anomalous position in Delhi. Somehow or other, in spite of calling Delhi a State, Delhi has not been given the power of the State. Law and order is entirely in the hands of the Central Government. The Delhi Police Commissioner is under the Central Government. All the land in Delhi is under the Ministry of Urban Development. For anything new to be done in Delhi, we need the permission of the Ministry of Urban Development. As a result of

this, the Government in Delhi – earlier Chief Ministers have lamented – is a toothless Government. Since Shri Jaitley is from Delhi, he will appreciate this problem. Let this new Government think of making Delhi a full-fledged State. Delhi is in a very anomalous situation where Delhi is neither a fish nor fowl. It is neither fully a Union Territory nor is it a State. Delhi has to be rescued from this situation.

We, in other metropolis of India, are envious of Delhi. Delhi being the capital, a lot of money flows into Delhi. It is not a healthy sign if somebody is red in the face. It is rather an unhealthy sign. Blood should flow through the body. The Central Government funds have been given liberally to Delhi. The other metropolises like Mumbai, Kolkata or Chennai or Bangaluru or Hyderabad have not received similar amounts of money.

Look at the institutions in Delhi. Delhi has the IIT fully run by the Central Government. Of course, Delhi is the Capital of the country. Delhi has the All India Institute of Medical Sciences. It is fully run by the Centre. Delhi is also having the best metro system in the country. Thanks to the vision of one Shri Sreedharan who single-handedly took up the construction of Delhi Metro. Delhi Metro which is a joint venture between the Union Ministry of Urban Development and the Delhi Government is really our pride. It is providing a great relief to the people of Delhi. Until the Metro was there and it has expanded, the transport problem of Delhi would have been insolubly unbearable. Metro has released everybody from this.

Even in the sphere of higher education, Delhi has a few of the best universities in the country, all run by the Central Government. Delhi University is a Central University. Jawaharlal Nehru University is a Central University. Now, the SAARC University has been formed. Dr. Ambedkar University is there. So, Delhi has been gifted with everything possible. We are all part of this because we are citizens of this country. Delhi is also the Capital of the country.

But what has really happened to Delhi? If it was not for the Supreme Court, successive Governments in Delhi, whether there or at the Centre have not done enough for Delhi. The polluting industries were removed from core areas of Delhi because of the Supreme Court order. Even, the CNG buses were introduced in Delhi again because of the Supreme Court orders. What have successive Governments done in Delhi? This is a matter that we have to take stock of, since we are discussing this in Parliament. Have we made Delhi a world class city? Delhi is world class only in the Lutyen's Zone. Outside, it has still not regularised *jhuggi-jhonpari* clusters. The common people of Delhi suffer from lack of drinking water. Electricity supply in Delhi has been given to private companies run by Tatas and Reliance, but that has not improved the state of electricity distribution in Delhi.

In this Budget, Mr. Jaitley has given Rs.17,700 crore for Plan. Of that, Rs.3,672 crore extra is Central grant-in-aid special for Delhi, Health – Rs.2,724 crore, Education – Rs.2,482 crore, Social Welfare – Rs.1,862 crore, Housing – Rs.2,154 crore, Water Supply is Rs.1,249.2 crore, Control of Pollution of Yamuna – Rs.1,750 crore, and Transport System – Rs.3,700 crore.

Look at Yamuna, Sir. It is the most-polluted drain you can find anywhere in the country. We have run governments from the city of Delhi and what have we done to the lifeline of Delhi? Is there any scheme of the Government to really clean up the Yamuna as it passes through Delhi? Is there any concrete plan given in this budget for providing enough drinking water especially to those living in Delhi slums? Is there any provision so that Delhi people will be spared of load-shedding? Kejriwal won because he promised people relief in all these matters, but he could not ...(*Interruptions*)

Sir, I would request the Finance Minister and the present government to take a fresh view of the total structure under which Delhi is governed. I would request him to really look at how problems of Delhi have multiplied over the years making it almost uninhabitable city excepting the high-cost colonies. Delhi is famous for gated colonies for the rich, but the poor and the ordinary people who provide the backbone of Delhi are left in the lurch. They have to travel 40 kilometres. Without the metro rail, I do not know where they would be? They live in *jhuggi-jhompri* clusters. I do not have the time to go into the problems of *Lal Dora* and all that. The anomaly about Delhi's Administration should be stopped once and for all.

Lastly, Sir, I have a small request to the Minister and I am sure he would accept it. He said that Delhi is inhabited by a lot of linguistic communities and it has four Academies of Urdu, Sindhi, Punjabi and Hindi. May I inform him that there are more than 100,000 Bengalis living in this city, not only in Chittaranjan Park but spread all over the city? We would like an Academy of Bengali in the city of Delhi in the interests of the large Bengali speaking community. There is already Lady Irwin School and other good Bengali schools in this city. Why should not there be a Bengali Academy in this city?

With this, Sir, I conclude.

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): Mr. Chairman, thank you for allowing me to speak on the Budget of National Capital Territory of Delhi. This is my maiden speech in Lok Sabha and I take this opportunity to thank my leader hon. Chief Minister Shri Navin Patnaik and the people of my Parliamentary Constituency Bargarh for giving me a chance to be a Member of this august House.

A number of hon. Members have spoken on so many problems of Delhi, so many aspects of Delhi, about the management, about the sewage systems, roads and communications but what about our heritage? I must focus on our heritage. If we look at our history and the archaeology of Delhi, it was the seat of administration for so many royal dynasties right from Mughals to Lodhis to Rajputs. There are many historical buildings but if we go to the surroundings of these monuments, we can see that they are in very bad condition. We can find a lot of encroachment, a lot of traffic, and human vandalism all around those historical monuments. So, I request the hon. Finance Minister to look into the matter to give a thrust to our heritage and to the monuments that we have inherited over so many years because if we lose them now, they will be lost for ever.

As you know, tourism is also linked to our monuments. There are no proper information centres in the monuments and in the building sites. So, I would like the Government to provide multimedia information centres and guided tours not only for the people of Delhi but also for the tourists and visitors who are coming to Delhi from different parts of the globe. They can know about our heritage, our culture and our past.

We have a number of museums in Delhi, right from the National Museum to Rail Museum, Archaeological Museum and so many other museums. But how many of us have seen those museums? There is no infrastructure, there is no basic facility, and there is no proper communication in these museums. So, I would request you to make them accessible to everybody and for proper popularisation of these museums, for application of proper

multimedia so that we can have a good flow of tourists and they can know of our heritage.

Regarding the Masterplan of Delhi, still there are a number of lacunae. We have taken into consideration all the VVIPs but what about the common man, who is coming to Delhi daily for his day to day work? We have not provided drainage system and proper drinking water facilities.

If you go to the New Delhi railway station, we have a lot of problems in the New Delhi railway station. This is the country's capital and we have no amenities. So, I request our hon. Finance Minister to focus on this aspect, to provide funds for the modernisation of the New Delhi railway station.

I would appeal through you for my State of Odisha. Of course, we have Odisha Niwas and Odisha Bhawan in Delhi but it is not sufficient for the people of Odisha who are coming to Delhi. I would request you to provide a piece of land to the people of Odisha in Delhi so that we can make a cultural complex in Delhi where we can exhibit our rich culture. Odisha is very rich in traditional arts like Sambhalpuri Odisha crafts. We can exhibit those things. The common man who is coming to Delhi could be accommodated here.

Delhi is not only for *Dilliwalas*. It is for the whole country. So, through you, I appeal to the hon. Finance Minister to look into the problems of the common man and the common citizens who are also a part of Delhi because in Delhi we have contributions from everybody, whether they are politicians, common citizens, technocrats, bureaucrats, masons, or students. So, keeping all in view, we have to give thrust to all aspects. So, I appeal through you to give emphasis to this matter.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Thank you for giving me the opportunity to speak on Delhi Budget.

Though I am from Telangana and Hyderabad, people may ask, why I am interested to speak about 'Delhi'. Everybody is interested in Delhi because it is the Capital of India. We have Hyderabad House in Delhi. We can boast of it because many international dignitaries visit that place to hold important meetings.

Hyderabad itself has contributed a lot. The Telangana State has contributed a lot to Delhi in many ways. One of them is Hyderabad House.

When I talk about Delhi, we have two 'Delhis' here – one is a Delhi where the Lutyens Bungalows are situated, where we have this Parliament also, which has vast greenery and wide roads with big cars, and the other 'real Delhi', stays outside 'this periphery of Delhi'.

The problems of Delhi are almost similar to what we have in any other metropolitan city. Delhi cannot be compared with any other metropolitan city because the people who come to Delhi are from Tamil Nadu, from Andhra Pradesh, from Telangana and from other places. So, Delhi is a miniature India. That is the reason why we must showcase Delhi in all respects, including welfare measures.

I wish to state that unfortunately Delhi has become the most polluted city in the world. We should not be proud of that. Delhi again is known as one of the unsafe places for women. This is also not good. We need to ponder over these points.

I want to bring to the notice of the hon. Minister, through you, Sir, certain issues pertaining to Delhi because it is now under the President's Rule.

Education is most important; I am happy that the Finance Minister stressed on health, education and social security. We generally call this as 'V3' – *Vidya, Vaidyam and Viyovriddhula Samkshemam.* These are the three aspects of any society that we have to take care. But when we see the education sector, in the Budget speech itself, he says these things.

Most of the migrant population are on a meagre salary. They do not have adequate finances to send their children to private institutions. As per the RTI requirement, there is a need for 500 schools, which is included in the Budget. As per my knowledge, the last Government has set the target of opening 100 schools and they had identified places for 32 schools. Unfortunately, there is a sanction for only 20 schools in this Budget. I request the Finance Minister to look at it very seriously because when you look at the middle class families, the most important thing for them is education. Most of their financial burden is on education. The Union Government has to take steps to open quality public schools. This is very important.

Secondly, for social sector also, they have allocated some money. But as far as my knowledge goes, the Delhi Government used to give Rs. 600 per month for the destitute women, whose number was about 12,000. But in this Budget, there is no mention about this. This is very important because the destitute women have no place to go. I request the Government to look into this matter very seriously.

Regarding pension, they give it to 3,90,000 persons. About 80,000 pension applications were pending earlier. But this Government has made it as 4,50,000. Still 20,000 people are waiting to get pension in Delhi.

Annasree was introduced earlier, but somehow, it is missing in this Budget. I want to bring this to the notice of the Finance Minister.

Pollution is most important; Delhi is becoming world famous on account of pollution. I request the Government to take immediate steps to control pollution because pollution is the unseen danger; it can affect the health of many people; it is something like 'weapon of mass destruction'. It is an unseen weapon. I request the Government to look into this.

A city would be proud of due to the rivers flowing in it. Unfortunately, River Yamuna is not to be seen! If one goes to any other State, one could see beautiful rivers. In Hyderabad, we have got Hussain Sagar, which is seen with beautiful bunds, statues, etc.

15.00 hrs.

That brings beauty to the city. Yamuna which should bring beauty to Delhi unfortunately is full of dirt. Like the Ganga project, the Government should give some financial commitment for the Yamuna also.

Another very important point is the safety of women but I do not want to go into the details of it. A provision for medical, legal and psychological counselling for rape victims is being made in the Budget. I would like to say that there are two types of victims; one who requires mostly medical help and the other who requires mostly psychological help. Hospitals are already flooded with a number of patients and when a rape victim is brought to a hospital, a number of people look at the innocent girl. So, I would request that separate homes or wards should be built so that a doctor, a lawyer or even a policeman can go to that place.

Before I conclude, I would like to say that Delhi is nothing but a miniature India. मेरे खयाल से दिल्ली में देश दिखना चाहिए। Each State has got certain symbols. For example, Hyderabad has got Golconnda, Charminar. Certain important places symbolise a State. When we come from airport to any part of Delhi, I would like Delhi to be seen as a reflection of India. At major intersections, flyovers or junctions, miniature State symbols should be erected so that when someone comes to Delhi he can feel proud of being a part of Delhi as his part of the State can be seen in Delhi.

As you know, after Hindi, Telugu is the largest spoken language. More important thing is we have two States with Telugu speaking persons. I would request the Union Government to immediately release funds so that a Telugu Academy can be started. Thank you very much for giving me an opportunity to speak.

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली) : धन्यवाद सभापति जी। दिल्ली के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने आठ दिनों के अंदर-अंदर केन्द्रीय बजट और दिल्ली का बजट सदन में प्रस्तुत किया। जब वित्त मंत्री जी बजट पढ़ रहे थे, मुझे विपक्ष की तरफ से एक-दो टिप्पणियां सुनाई दे रही थीं। सौगत राय जी जो अभी सदन में नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि यह चुनावी बजट है। मुझे खुशी हुई कि अनेक दलों के माननीय सदस्यों ने दिल्ली बजट पर चर्चा के दौरान हिस्सा लिया और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में सामने रख कर अपनी-अपनी बात रखी। दिल्ली वाकई में मिनी इंडिया है। दिल्ली में देश के हर राज्य के लोग रहते हैं।

15.04 hrs.

(Shri Konakalla Narayana Rao *in the Chair*)

सभापति जी, मैं दिल्ली के बजट पर कुछ कहूं, उससे पहले दो-तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि दिल्ली की आबादी इस वक्त ढाई करोड़ के करीब है और 2030 तक यह 3 करोड़ 60 लाख तक हो जाएगी। यह जो जनसंख्या का दबाव दिल्ली पर बढ़ता जा रहा है, पानी और बिजली पर भी इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। मुझे दुख होता है कि पिछली सरकारों ने पानी और बिजली की योजनाएं तो बनाई या विकास की योजनाएं बनाई, वे दीर्घकालीन योजनाएं नहीं थीं। आने वाले समय को ध्यान में रखकर पिछली सरकारों ने दिल्ली के लिए कोई प्लानिंग नहीं की थी। दिल्ली में जैसा कि अभी बताया गया, 1600 अनधिकृत कालोनियों में 45 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। 1200 के करीब हमारे यहां पर स्लम्स हैं जिनमें 5 लाख झुग्गियों में 30 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। साथ ही 360 गांव हैं जिनमें 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये जो 49 प्रतिशत की आबादी है, दिल्ली का जो विकास है, ये 49 प्रतिशत की आबादी को ध्यान में रखकर करना चाहिए।

सबसे पहले दीपेन्द्र जी ने बजट पर बोलना शुरु किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप हरियाणा के साथ-साथ दिल्ली के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। हरियाणा में कल ही आपके प्रदेश के एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है मगर आपको दिल्ली की ज्यादा चिंता हो रही है। इसलिए मुझे खुशी है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इन्होंने सबसे बड़ा असत्य जो बोला कि दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत कांग्रेस की सरकार ने की। जब 1995 में डीएमआरसी का रजिस्ट्रेशन हुआ, उस समय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वर्ष 1998 में जब उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, तब दिल्ली में हमारी सरकार थी। यह कैसे हो सकता है कि दिल्ली में कांग्रेस ने मेट्रो का निर्माण किया? वर्ष 1998 में, 2003 और 2008 में कांग्रेस बार-बार कहती रही कि दिल्ली में मेट्रो का निर्माण हमने किया। वर्ष 2002 में जब फेस-1 का उद्घाटन हुआ, तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस फेस-1 का उद्घाटन किया था। मुझे दुःख हुआ जब दीपेन्द्र जी ने निशिकांत दूबे जी के बारे में टिप्पणी की और कहा कि आप दिल्ली के नहीं हैं, क्या आप दिल्ली के हैं? क्या आप दिल्ली के बारे में जानते हैं? मगर मैं चाहता हूं कि पूरा सदन, हर पार्टी दिल्ली के बारे में बोले, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, यहां पर 365 दिन में से 150 दिन आप सभी यहां रहते हैं, यह आपका दूसरा घर है, इसकी चिंता आपको करनी चाहिए और आपको अपने एमपी लैड फंड में से भी 50-50 लाख रुपये दिल्ली के बजट में देने चाहिए। ...(व्यवधान) जैसे ये 55 साल इस देश को कहानी सुनाते आये हैं, 15 साल इन्होंने दिल्ली को कहानी सुनाई है, वैसे ही ये यहां पर कहानियां सुना रहे थे। वर्ष 2013 का जो बजट आया, उसमें इनके वित्त मंत्री जी ने कहा था कि 100 नये स्कूल देंगे, मगर उसी दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में नये स्कूलों और अस्पतालों के लिए हमारे पास जगह नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती थीं कि हमारे पास जगह नहीं है, ये अपने बजट में कहते थे कि 100 नये स्कूल देंगे। 15 सालों में इन्होंने कितने नये स्कूल खड़े किये? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। 15 सालों में क्या इन 1600 कॉलोनियों की इन्होंने चिंता की? दिल्ली की 800 कॉलोनियों में आज भी सीवर और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। 15 सालों तक इनकी नींद नहीं खुली। अभी इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हमने 840 कॉलोनियां पास कीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर दिल्ली में एक भी कॉलोनी पास हुई हो, अगर एक भी कॉलोनी में मकान का नक्शा बनता हो, अगर एक भी कॉलोनी में रजिस्ट्री होती हो।

यहां अभी माननीय सोनिया जी नहीं बैठी हैं लेकिन वर्ष 2008 के चुनाव में, छत्रसाल स्टेडियम में इन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी जी के हाथों से दिल्ली की सारी कॉलोनियों को प्रॉविजनल सर्टिफिकेट दिलवा दिये, शायद यह उनकी जानकारी में नहीं होगा, वे तो सर्टिफिकेट देकर आ गयी थीं, मगर एक भी कॉलोनी दिल्ली में पास नहीं हुई। ये कहानियां सुनाते थे लेकिन कॉलोनी एक भी पास नहीं हुई। अब हमने अपने बजट में कहा है कि हम 50 कॉलोनियों में पीने का पानी और 95 कॉलोनियों में सीवर की व्यवस्था करेंगे।

सीडब्ल्यूजी गेम्स हुए, कॉमनवैल्थ गेम्स हुए, आपने कॉमनवैल्थ गेम्स में 5000 नयी बसों को खरीदना था लेकिन कुल 1100 बसों को ही आप खरीद पाए। आज दिल्ली में 5000 बसें चलती हैं लेकिन वर्ष 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में 11000 बसों की जरुरत है। आप 15 सालों तक क्या करते रहे, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 15 सालों में क्या एक भी नयी यूनिवर्सिटी बनाई? अम्बेडकर कॉलेज था उसकी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बना दी। आईपी यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया, डीसी कॉलेज था उसे यूनिवर्सिटी बना दिया लेकिन अपने इनीशिएटिव से इन्होंने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। आप बताएं कि आपने अपने समय में कितने कॉलेज दिल्ली में बनाकर दिये? मेरे पास बच्चे आते हैं, उन्होंने 95 प्रतिशत नम्बर लिए हैं लेकिन उन्हें कालेज में दाखिला नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे बाहर जा कर पढ़ने को मजबूर हैं, इसलिए ही वित्त मंत्री जी ने केंद्रीय बजट में जो पूरे देश में आईआईटी, आईआईएम खोलने की बात कही है, ताकि दिल्ली की जनता पर शिक्षा का जो दबाव है, वह कम हो।

इन्होंने बिजली की बात भी कही है और बहुत चिंता भी जताई है। वर्ष 2002 में जब बिजली का निजीकरण हुआ था, कांग्रेस के ही एक एमएलए डॉ. एस.सी. वत्स थे। उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी वत्स कमेटी बनी थी। सी.ए.जी. ने उस कमेटी की रिपोर्ट को महेनजर रखते हुए कहा था कि 8500 करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ है। कांग्रेस के विधायक ने कमेटी की रिपोर्ट में कहा था कि बिजली के निजीकरण में घोटाला हुआ था। आज अगर हम दिल्ली के 85 प्रतिशत गरीब लोगों के बिजली के बिल कम करने की बात कहते हैं, तो इन्हें तकलीफ होती है।...(व्यवधान) दीपेन्द्र जी की बातों के कारण मेरे पांच मिनट ज्यादा लग गए हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि मुझे बोलने के लिए ज्यादा समय दिया जाए। इन्होंने लाल डोरे की बात कही है। पन्द्रह साल में इन्होंने कितने गांवों का लाल डोर बढ़ाया है? इन्होंने पन्द्रह साल राज किया और हर घोषणा-पत्र में कहानी सुनाते रहे और दिल्ली की जनता विश्वास करती रही, मगर एक भी गांव का लाल डोरा नहीं बढ़ा। हमारी सरकार वर्ष 1993 से 1998 के बीच में थी। हमने चार गांवों में चकबंदी की थी। एक-एक गांव में चाहे वह बामडोली गांव था, चाहे कंझावला गांव था, एक-एक गांव वालों को 2100-2100 गज के प्लाट दिए थे। 300-300 गज के प्लाट इंडस्ट्री के लिए दिए थे, लेकिन इन्होंने किसी एक भी गांव में प्लाट नहीं दिया। अभी भी 14 हजार एप्लीकेशन पेंडिंग हैं, जिन गांव वालों की जमीनें एक्वायर हो चुकी हैं, आज तक उन्हें अल्टरनेटिव प्लाट नहीं मिला है। दिल्ली सरकार कहती रही कि हमारे पास जमीन नहीं है। ये कहते हैं इन्हें गांव की चिंता है? मैं दिल्ली सरकार के स्कूलों के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि मार्च में सैशन शुरू होता है और जुलाई तक उन्हें किताबें नहीं मिलती हैं जबकि प्राइवेट स्कूलों में किताबें मार्च महीने में ही मिल जाती हैं। यह दिल्ली में शिक्षा का हाल है जो पन्द्रह साल बाद हमें उत्तराधिकार में मिला है।

महोदय, the world is changed by examples, not by opinions. कहानियां सुनाने या कहने से देश नहीं चलता है, दिल्ली नहीं चलती। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। विश्व में सबसे सुन्दर राजधानी इसे बना कर दिखाना है। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि न केवल दिल्ली बजट पर बल्कि केंद्रीय बजट में उन्होंने दिल्ली के लिए 500 करोड़ रुपए वॉटर रिफार्म्स के लिए दिए। 200 करोड़ रुपए पॉवर रिफार्म्स के लिए दिए। रेणुका डैम का प्रोजेक्ट है। पानी के ऊपर इन्होंने क्या काम किया है? स्कूलों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। आज दिल्ली में पानी की डिमांड 1100 एमजीडी है लेकिन दिल्ली की जनता को 800 एमजीडी पानी मिलता है। रेणुका डैम प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में बन रहा है उसके लिए वित्त मंत्री जी ने 50 करोड़ रुपए दिए हैं और उससे दिल्ली की जनता को 275 एमजीडी पानी अधिक मिलेगा। दिल्ली पुलिस को 394 करोड़ रुपए ज्यादा दिए। नेशनल पुलिस मेमोरियल के लिए 50 करोड़ रुपए दिए। वॉर मेमोरियल, वॉर म्यूजियम के प्रिंसिस पार्क इंडिया गेट के पास बनना है, मैं विदेश में जाता हूं और वहां मैं म्यूजियम देखता था और उनके इतिहास को जानता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 66 साल में आज तक हमारे देश में क्या-क्या लड़ाइयां हमने लड़ी हैं, कैसे उन्हें जीता है, उनके बारे में हमारे युवाओं ने इतिहास में नहीं पढ़ा है। जेजे कलस्टर को आपने सीएसआर स्कीम से जोड़ने की बात कही है। मेट्रो के लिए 3470 करोड़ रुपए दिए हैं। मैं वह बता रहा हूं जो केंद्रीय बजट में दिल्ली को दिया गया है।

मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि दिल्ली में एक रुपये का भी नया टैक्स दिल्ली की गरीब जनता के ऊपर उन्होंने नहीं डाला है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं और पिछले 8 साल का आंकड़ा बताऊं,...(व्यवधान) सीएजी की बहुत रिपोर्टें आपके खिलाफ हैं। वर्ष 2005 में 20619 बैड सरकारी अस्पताल में थे और 2013 में 22919 बैड थे। केवल 2300 बैड बढ़ा पाए। यह मैं पिछले 8 साल की बात बता रहा हूं। यही संख्या प्राइवेट अस्पतालों में 7000 बैड की बढ़ी है। कांग्रेस ने 2012-2013 के बजट में प्रपोज किया था कि हम एक साल में 2900 बैड बनाएंगे। लेकिन पिछले 8 सालों में दिल्ली की जनता को केवल 2300 बैड ही इन्होंने दिये। मगर मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने रोहिणी में मेडिकल कॉलेज के लिए 100 सीटों का प्रावधान किया और 2015 तक पहला बैच भी शुरु हो जाएगा। लोक नायक अस्पताल को गुरु तेग बहादुर अस्पताल को आपने मॉडल हॉस्पिटल बनाने की बात कही है। आपने दक्षिण दिल्ली में, ग्रामीण क्षेत्र में मल्टी स्पेशलटी हॉस्पिटल बनाने की बात की है। आपने 30 नयी डायलिसिस यूनिट और 110 नयी कैट्स एम्बुलेंस को शुरु करने की बात कही है। आपने 2724 करोड़ रुपया स्वास्थ्य के लिए दिया है। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही दुख का विषय है कि आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में, 30 प्रतिशत स्कूलों में आज शौचालय की सुविधा नहीं है। यह इन्होंने 15 साल में दिया है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में दिल्ली के सभी स्कूलों में हम शौचालय को ठीक करने की सुविधा देंगे। आपने तीन कॉलेजों के लिए दीन दयाल उपाध्याय के लिए 151 करोड़ रुपया, ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The time is up. Please conclude. There are many Members more to speak.

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : सर, हमारे दिल्ली के दूसरे सदस्य मनोज जी केवल 5 मिनट बोलेंगे। मेरी उनसे बात हुई थी। उनके पांच मिनट आप कृपया मुझे दे दें। ...(व्यवधान) आपने 225 करोड़ रुपया स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्कीटैक्चर डिजाइन के लिए दिया। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने दिल्ली में सीनियर सैकेंडरी स्कूल जो दो विधान सभा में नहीं थे, वह आपने खोलने की बात कही है। सामाजिक सुरक्षा की अगर मैं बात करूं, इनको बड़ी चिंता थी कि कांग्रेस की जब सरकार 2013 में थी तो इन्होंने वृद्धावस्था पेंशन खत्म कर दी। जो हमारे बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिलती थी, वह कांग्रेस की सरकार ने खत्म कर दी और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसने भी वह व्यवस्था शुरु नहीं की। मैं दिल्ली में विधायक था। मेरे पास बुजुर्ग पेंशन के लिए आते थे। मैं उनको कहता था कि आपने आम आदमी पार्टी को वोट किया मगर इन्होंने वृद्धावस्था पेंशन शुरु नहीं की। हमने न केवल उस पेंशन को शुरु किया है बल्कि उसकी संख्या को भी बढ़ाकर हमने 4 लाख 30 हजार कर दिया है और उसमें 538 करोड़ रुपये से बढ़ाकर हमने बजट को 600 करोड़ रुपये दिया। बहुत ही शर्म की बात है कि दिल्ली सरकार एक आशा किरण केन्द्र चलाती है जिसमें मेंटल रिटार्टेड यानी जो हमारे मानसिक रोगी हैं, उनका वहां पर इलाज किया जाता है। उसकी कैपेसिटी 350 है मगर वहां पर 906 रोगी भर्ती हैं। 350 की कैपेसिटी में इन्होंने 906 डाल दिये मगर एक भी नया केन्द्र नहीं बनाया। हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि तीन नये ऐसे केन्द्र खोले जाएंगे जहां पर इनका इलाज होगा।

वर्किंग वूमैन हॉस्टल के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने 15 साल में केवल दो बनाये। आज वर्किंग वूमैन की संख्या दिल्ली में कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमने 6 नये हॉस्टल बनाने की बात करी है। यह बहुत ही दुख की बात है कि भारत की राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और 2014 के जनवरी के ठंड के महीने में 170 लोगों की मृत्यु हुई। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम 7 नये नाइट शैल्टर बनाएंगे। ...(व्यवधान)

मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि जो 1984 के दंगों के विक्टिम थे, आज वे बहुत ही बुरी हालत में हैं। 1984 दंगों के जो विक्टिम हैं, उनके वैल्फेअर के लिए आपको कम से कम 5 करोड़ रुपये इस बजट में देने पड़ेंगे और जो उनके दोषी थे, उनको सजा दिलानी पड़ेगी। यह मैं आपसे अपना निवेदन करता हूं।

शहरी विकास के लिए अनधिकृत कॉलोनियों को पास कराना बहुत जरूरी है। द्वारिका में पानी नहीं है। यहां पर हमारे सदस्यों के बहुत सारे रिश्तेदार रहते होंगे। वहां पर पानी की बहुत कमी है। द्वारिका में नयी कॉलोनी बसी है। यहां पर 15 सालों से कांग्रेस क्या करती रही? वहां पर लोग रोज सड़क के ऊपर बैठ जाते हैं। मैं कहूंगा कि द्वारिका के लोगों के लिए आप पीने के पानी की व्यवस्था कराइए।...(व्यवधान) सर, एक मिनट दे दीजिए। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इन्होंने पिछले 15 साल में 6000 करोड़ रुपये यमुना की सफाई में लगाये। आज यमुना की हालत देख लीजिए। ...(व्यवधान) The secret of change is to focus all your energy not on fighting the old but on building the new. हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम एक नया भारत बनाना चाहते हैं। मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। मैं किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय सदस्य सौगत राय जी ने बताया कि यह लुटियन की दिल्ली नहीं है, दिल्ली में पूर्व से पश्चिम से बहुत लोग रहते हैं, यही असली दिल्ली है। मैं बहुत दूर से दिल्ली में आया हूं और दिल्ली को देखता हूं तो लगता है यही असली दिल्ली है।

I have been coming to Delhi since early eighties. There are people from North-East and other parts of the country living in Delhi. वे लोग यहां आते हैं। यहां आम आदमी को जो कठिनाइयां हो रही हैं, मुझे उसके बारे में चर्चा करनी है। दिल्ली के बजट में 36,766 करोड़ की राशि रखी गई है I think that is less than the provision of previous year's Budget.

अब दिल्ली में पीने के पानी की बात आती है। मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट और जनपथ की बात नहीं कह रहा हूं लेकिन दिल्ली की अन्य बस्तियों में पीने के पानी की कमी है इसलिए यहां लोगों को जल माफिया की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इलैक्ट्रिसिटी में सब्सिडी का वादा किया है लेकिन बजट से पहले 8.32 परसेंट रेजिडेंशियल और 9.5 परसेंट कमर्शियल पर रेट बढ़ा दिया गया। 260 करोड़ की सब्सिडी देने के बाद भी यह जीरो प्वाइंट पर भी नहीं आएगा, इस तरह यह सब्सिडी कुछ भी नहीं है।

अब मैं सेनिटेशन के बारे में बताना चाहता हूं। रिसेंट रेगुलराइज कालोनियों का दृश्य ऐसा है कि महिलाओं को भी ओपन में डेफिकेशन करना पड़ता है। मैं यह बात दिल्ली से चुने हुए माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कह रहा हूं। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो हमने दिल्ली को वर्ल्ड सिटी बनाने का जो सपना देखा है वह कभी पूरा नहीं हो पाएगा।

Health facilities are woefully inadequate in the rural areas and in the *bastis*. That should also be improved. In the dispensaries there is no medicine and there is no staff. We have been receiving a lot of complaints regarding that.

As far as education is concerned, definitely we are proud of the Delhi University, the Jawaharlal Nehru University and so many other institutions. But what will happen to the children of poor people if more schools and more colleges are not set up in Delhi? So, I think that should be taken care of.

Then, I come to housing. अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने घोषणा की है कि वर्ष 2022 में सबको घर दिया जाएगा। दिल्ली शहर हमारा गौरव है, हमारे देश की राजधानी है। दिल्ली में लोगों को सड़कों और फुटपाथ पर सोना पड़ता है। हमें इस तरफ ध्यान देना होगा।

I come from North-East. The people of North-East have started coming to Delhi for education, jobs, etc. But there is a huge crisis for

accommodation. So, we need one complex for the North-East people, which will be showcasing their culture, food, etc. I think that matter can be considered by adding funds from other Ministries also in the Delhi Budget.

With these words, I conclude.

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Delhi Budget. Delhi is the pride of our nation. It has grown over centuries. Delhi is the Capital city of our country and over decades we have been promoting our culture and tradition throughout Delhi, the Capital. I am a new comer to Parliament. Sir, many of my senior colleagues spoke about the Delhi Budget; they spoke about the schools; they spoke about the institutions. But I would like to highlight a few factors in this House.

One is about the transportation problem in Delhi. There are people who are coming from different States to Delhi pertaining to issues of administration and other political issues. Delhi being the capital of the country, there is a lot of traffic congestion and there is a lot of pollution in the City of Delhi. Hence I request the hon. Finance Minister to allocate a certain Budget for Delhi to deal with the transportation problem by providing more metro facilities as also other facilities that can be of importance to the common man of Delhi.

I would also like to say that this is a place which has emerged over centuries. Many rulers have ruled this nation and they have left behind a lot monuments of heritage value and ancestral value. So, I would request the hon. Finance Minister to provide enough resources in the Budget to take care of these monuments, protect them and pass them on to the future generations. By this way, we can promote our culture, tradition and pass it on to the next generation.

Sir, I am not sure whether I can raise this topic in this discussion. Being a fresher in this House, I would like to say that accommodation for the Members of Parliament is one more important problem which we have been facing. So many cottages have been allotted. We are only a thousand people in Parliament today. In spite of this, proper housing facility is not provided to all of us. Many of us have even now been fighting for accommodation. Hence, I request the hon. Finance Minister to give utmost importance to this because we are a thousand people sitting in Parliament as the law-makers of this country. Today, many of the houses that have been provided to us are in a very bad shape and they are not even in a favourable condition to live in. Hence I request the hon. Finance Minister to allocate a certain Budget for the repairs of these buildings as well as providing proper accommodation to us so that as long as our stay is here, when we represent our constituency in Delhi, we can find it a little bit more comfortable and we can have a peaceful living in Delhi.

Lastly, I would like to thank the Chair for giving me this time. I am concluding with these few words.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, आपने दिल्ली के बजट पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस बजट के फेवर में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, श्री नरेन्द्र मोदी जी, ऑनरेबल फाइनेन्स मिनिस्टर, श्री अरुण जेटली साहब, महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति जी, जिनके माध्यम से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। इस बजट में विजन है। आजादी के बाद देश जब 75 साल का होगा तो जो हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हर व्यक्ति को मकान जो उसकी बेसिक अमेनिटीज है, उसे और देश के लोगों को मिलेंगी। जो साठ सालों में मेरे सामने बैठे बंधु नहीं दे पाये थे, लेकिन 2022 तक हर व्यक्ति को ये फैसिलिटीज मिलेंगी। मैं इस बजट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने यह नहीं कहा कि अच्छे दिन एक महीने में आयेंगे या चार महीने में आयेंगे, मोदी जी ने कहा था, आपने कांग्रेस को साठ साल दिये, हमें साठ महीने दे दीजिए, अच्छे दिन निश्चित रूप से आयेंगे। यहां हमारे भाई बैठे हैं, भगवंत मान जी भी बैठे हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात देखिये, अभी मैंने कांग्रेस के लोगों, आम आदमी पार्टी का एक होर्डिंग देखा, एक जिराफ बना रखा है, उसकी गर्दन पर गधा बैठा रखा है और गधा कह रहा है कि अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे। हम कहना चाहते हैं कि गधों को अच्छे दिन थोड़े ही दिखाई देते हैं, अच्छे दिन तो इंसानों को दिखाई देंगे। मैं इनकी सोच के बारे में बता रहा हूं, महिपालपुर चौक और दिल्ली में कई जगहों पर ऐसे होर्डिंग लगा रखे हैं। इसीलिए मैं अपने बंधुओं को बता देना चाहता हूं कि हमारे एआईडीएमके के बंधु ने कहा था कि हमारे यहां जयललिता अम्मा जी ने टैक्स फ्री बजट पेश किया है। भाई दिल्ली के अंदर यह भी टैक्स फ्री बजट है। इस बजट में भी एक पैसे का टैक्स नहीं लगाया गया है। हमारे तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद बंधु ने कहा था, वह अभी यहां नहीं हैं, शायद चले गये हैं, वह भी कह रहे थे कि दिल्ली के बजट में केन्द्र से स्पेसिफिक प्रोविजन किया गया है, जो अन्य मैट्रोपोलिटन सिटीज को नहीं दिया गया है। आपनी बात को वे खुद ही कोंट्राडिक्ट कर रहे हैं। खुद ही कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लैण्ड, पुलिस, यूनिवर्सिटी सब के ऊपर केंद्र का अधिकार है। जब केंद्र का अधिकार है तो केंद्र तो पैसा देगा ही देगा। वह दिल्ली के बजट से क्यों कटेगा। जब दिल्ली नैशनल कैपिटल है और यहां पर सारी चीज़ों का होल्ड केंद्र का है, केंद्र की तरफ से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने पैसा दिया है तो यह बड़ी सोच रख कर किया है। 15 साल यह आपको सोचना चाहिए था कि आपने दिल्ली के बारे में क्या किया है? आपको चिंता करनी चाहिए थी। ...(व्यवधान) मैं इनको बताना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) सर, अब मैं इस बजट पर आना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) सर, जीवन हैल्थ से शुरू होता है। अगर व्यक्ति का जीवन स्वस्थ है, व्यक्ति स्वस्थ है तो सब ठीक रहता है। सर, सन् 1998 में, केंद्र में हमारी सरकार थी, ...(व्यवधान) सन् 1998 के अंदर केंद्र में एनडीए की सरकार थी, तब डेढ़ सौ करोड़ रूपये की लागत से हमने दो कैंसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक ईस्ट दिल्ली के लिए, दूसरी जनकपुरी में वैस्ट दिल्ली के लिए जमीन दी थी। सन् 1998 में दिल्ली के अंदर इनकी सरकार आ गई। सन् 1998 से लेकर आज तक डेढ़ सौ करोड़ रूपये की लागत से केवल दो अस्पताल बना पाए। दोनों अस्पताल पेशंट की बाट जोह रहे हैं। उसे पीपीपी के अनुसार चलाया जाए या कैसे चलाया जाए, they have not taken decision till today कि उस हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशंट एडमिट हो जाए। सर, हमारे माननीय वित्त मंत्री साहब ने कहा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में साऊथ दिल्ली की रूरल बैल्ट के अंदर एक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे। सर, उन्होंने कहा है कि रोहिणी में एक मैडिकल हॉस्पिटल कॉलेज बनाएंगे और इसी साल के अंदर उसमें मैडिकल के छात्रों की भर्ती करेंगे। यह विजन के अनुसार चलने वाली सरकार है। यह तो मैं इनकी कथनी और करनी बता रहा हूँ।

भाई हुड्डा साहब चले गए हैं, वे भी बहुत कुछ ऐसे कह रहे थे कि जैसे लोग नाना-नानी की कहानियां सुनाते हैं। वे उन कहानियों को सुना रहे थे। उनको उन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हरियाणा के बारे में वे जानते होंगे और दिल्ली की चिंता कर रहे हैं। हरियाणा ने आज तक 15 वर्ष में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, मुनक नहर से दिल्ली को 80 एमजीडी पानी उसके हिस्से का मिलना चाहिए, वह पानी आज तक नहीं दिया। हमारे लॉ के अंदर है, कहीं कोई बेसिक रेक्युज़ जैनरेट होते हैं, यमुना नदी हमारी दिल्ली से हो कर गुजरती है, यमुना में पानी हरियाणा से हो कर आता है, हमारे हिस्से का मुनक नहर का पानी, जब स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चार सौ करोड़ रूपये दिए थे कि दिल्ली में पानी आ जाए और 80 एमजीडी पानी की जो लीकेज होती थी, 15 वर्ष में उसका हमें जो बचा हुआ पानी मिलना चाहिए था, हुड्डा साहब की सरकार दस साल से हरियाणा में है, केंद्र में इनकी सरकार थी, बार-बार कोर्ट ने सन् 2011 में, 2014 में इंटरफेयर किया है। कोर्ट के इंटरफेयर के बावजूद भी मुनक नहर से इन्होंने पानी नहीं दिया। दिल्ली की चिंता करने की बात कर रहे हैं।

सर, मैं पानी के बारे में इनको बताना चाहता हूँ कि 15 वर्ष के अंदर इन्होंने कोई योजना ही नहीं बनाई। दिल्ली में दिन प्रति दिन पॉप्युलेशन बढ़ती जा रही है। दिल्ली देश की राजधानी है। देश के हर क्षेत्र के व्यक्ति का अधिकार है कि वह दिल्ली में आ सकता है। दिल्ली में प्रति वर्ष पांच लाख लोग बाहर से आते हैं। अभी मुझसे पहले हमारे बंधु प्रवेश जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर 1100 एमजीडी पानी की आवश्यकता है। 800 एमजीडी पानी जनरेट होता है। 744 एमजीडी फिल्टर से, 80 एमजीडी रैनी कुएं से और 2750 दिल्ली के अंदर ट्यूबवेल लगे हुए हैं। 15 साल में 255 एमजीडी पानी, जो लीकेज की वजह से चला जाता है, सर, मैं नहीं कहता, यह एक लीकेज एण्ड डिटेक्टिव एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में 35 प्रतिशत पानी लीकेज के द्वारा चला जाता है। आप सैंटर में बैठे हुए क्या करते रहे? हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने इसकी चिंता की और पांच सौ करोड़ रूपये उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए दिए, कि केवल 15 प्रतिशत लीकेज होनी चाहिए। जो पानी नालियों में बह जाता है, वह लोगों को पीने के लिए मिलना चाहिए।

सर, इसमें ज्यादा न जाते हुए मैं नैक्सट स्टेज पर आते हुए एजुकेशन के बारे में बोलना चाहता हूँ। सर, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार एक क्लास के अंदर 40 बच्चे होने चाहिए। पिछली बार इन्होंने वादा किया था कि सौ स्कूल खोलेंगे। हम मुंगेरी लाल की तरह सपने नहीं दिखाते। हमने कहा है कि एक साल में 20 खोल पाएंगे तो 20 ही कहा है। सर, इन्होंने अपने मैनिफैस्टो के अंदर 100 स्कूलों के लिए वादा किया था। Ã ाहोदय, दस स्कूल भी नहीं खुले। आप यहां से कोई कमेटी नियुक्त करें, एक सैक्शन के अंदर देश की राजधानी दिल्ली में नब्बे से सौ बच्चे बैठते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए इससे बड़ी शेमफुल बात नहीं हो सकती कि एक सैक्शन के अन्दर सौ बच्चे हों। दिल्ली के अंदर बीस हजार टीचर्स की कमी है, पन्द्रह वर्षों में इन्होंने टीचर भर्ती नहीं किए। एक स्कूल है, जे ब्लॉक, सपना विहार का मैं एग्जांपल देता हूं, वहां बच्चे सत्ताईस सौ हैं और मात्र सात टीचर हैं। मैं इसको ऑन दी फ्लोर बोल रहा हूं। वहां केवल सात टीचर हैं, कैसे बच्चा एजूकेशन लेगा? ये गरीब का हित करने वाली बात करते हैं, ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं, दिल्ली यूनीवर्सिटी के अंडर पन्द्रह सालों में एक भी नया कॉलेज नहीं खुला है। एक लाख बच्चे हर साल 12वीं पास करके आते हैं। गरीब का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला है, वह 90-95 परसेंट नंबर कैसे ले लेगा? न उस बच्चे को 95 परसेंट नंबर मिलेंगे और न ही उसको कॉलेज में एडमीशन मिलेगा। इसका जिम्मेदार यदि कोई है तो ये लोग हैं, जो पन्द्रह साल से, दस साल से यूपीए के रूप में यहां बैठे हुए थे। उसका कोई और जिम्मेदार नहीं है। ये इसीलिए शोर मचा रहे हैं कि यह इलेक्शन बजट हो गया। आपको तो ताली बजानी चाहिए थी। हमारे एक साथी चले गए, तारिक भाई, वे कह रहे थे कि अरे यह तो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने घोषणा कर दी। इससे बड़ा संगठन और पार्टी, दल क्या हो सकता है कि जो अपने मैनिफेस्टो को ही लागू कर दे, इसके लिए तो उनको हमें धन्यवाद करना चाहिए था। वे खुद ही कह रहे थे कि यह बजट नहीं, यह मैनिफेस्टो है बीजेपी का। तारिक जी कह रहे थे कि यह इलेक्शन बजट है। अरे, यह चाहे इलेक्शन बजट हो, चाहे कोई भी बजट हो, अगर जनता को सुविधा और फैसेलिटीज मिल रही हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मोदी जी ने कहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वह आ जाएंगे और इनके बोरिया-बिस्तर बंध जाएंगे, शायद इनको इस बात की चिंता है।

महोदय, मैं तीसरी बात यूआरडी मिनिस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं। एक जेएनएनयूआरएम नाम की स्कीम है, उस स्कीम के अंदर केवल गुजरात स्टेट ऐसा है, जहां दस के दस प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए। हमारे दिल्ली के हिस्से में छः सौ करोड़ रूपये आए थे। छः सौ करोड़ रूपए में कॉमनवेल्थ गेम्स के इंवल्यूड होने के बाद भी केवल 148 करोड़ रूपए की लागत से ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज वन और फेज टू है, जहां से मैं तीन बार से एमएलए हूं। वहां पर वे डेढ़ सौ करोड़ रूपए तो खर्च हो गए हैं, लेकिन जेएनएनयूआरएम के पैसे दिल्ली की शीला सरकार के समय में साढ़े चार सौ करोड़ रूपए वर्ष 2012 में लैप्स हो गए। इन्होंने वर्ष 2007 में पॉलिसी बनाकर वह पैसा दिया था, जेएनएनयूआरएम के अंदर डेवलपमेंट के लिए आप वह पैसा लगाते। दिल्ली के अंदर सोलह सौ अनाधिकृत कॉलोनीज हैं, एक कॉलोनी भी पास नहीं हुयी। माननीया सोनिया जी अगर यहां पर होतीं, तो मैं उन्हें बताना चाहता था कि मुंगेरी लाल के सपने दिखाते हो। इनकी पार्टी की सर्वोच्च लीडर वर्ष 2008 में रिबन काटकर रामलीला मैदान में प्रोविजनल सर्टीफिकेट अनाधिकृत कॉलोनीज के लोगों को दे जाती हैं कि हम तुम्हारी कॉलोनियों को पास कर देंगे, आप हमें वोट दे देना। इस वजह से वर्ष 2008 में इनकी सरकार आ गयी। लोगों को इन्होंने गुमराह किया।

महोदय, मैं दो मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं। इनको दर्पण भी दिखना चाहिए, देश की जनता को भी पता लगना चाहिए कि मोदी जी की सरकार, उनका विजन और इन लोगों का पिछले लंबे समय से विजन क्या है? मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनकी स्थिति क्या है? मैं एनवायर्नमेंट के ऊपर आना चाहता हूं।

महोदय, आप घंटी बजा देते हैं तो मैं कन्फ्यूज हो जाता हूं। आप दो मिनट घंटी मत बजाइयेगा, मैं दिल्ली के बारे में पहली बार बोल रहा हूं और दिल्ली की पीड़ा मेरे पास है। ट्रांसपोर्ट के मामले में अभी हुड्डा साहब कह रहे थे, वे यहां होते तो अच्छा होता, वे कह रहे थे कि उन्होंने 1300 बसें चलाने की बात कही थी, कम से कम उसमें 20 बसें तो बढ़ा देते, 1320 तो कर देते, यह तो हमारी ही पॉलिसी है। भाई, हम आपकी तरह मुंगेरी लाल के सपने लोगों को नहीं दिखाते हैं, जो कर सकते हैं, उन 1300 बसों का हमारे पास प्रोविजन है। सबसे पहली बात तो मैं कहना भूल ही गया, इनका लास्ट ईयर एजुकेशन का बजट आया 2,046 करोड़ आया, हमने उसको प्लस करके 2,482 करोड़ किया। हमने उसमें 400 करोड़ रूपया बढ़ाया। हमने हर डिपार्टमेंट का बजट बढ़ाकर पेश किया है। हमने पावर का बजट पेश किया, एनर्जी का बजट पेश किया, पिछली सरकार का पिछले साल का बजट 2,000 करोड़ था, हमने 675 करोड़ उसमें अतिरिक्त दिया है।

मैं सब्सिडी की बात भी दोहराना चाहता हूं, जिसे पूर्व के वक्ताओं ने बोला है, इन्होंने कहा कि एक जेब से निकालकर दूसरी में दे रहे हैं। यह इनकी प्रवृत्ति रही है, एक जेब से निकालकर लोगों को गुमराह करने की। केन्द्र सरकार से डायरेक्ट सब्सिडी इस दिल्ली के बजट को 20 साल में कभी नहीं मिली, केवल जो पैसा इन्होंने जो पिछली बार सब्सिडी दी थी, हमारे भाई साहब भगवंत मान जी बैठे हैं, वे भी उस दिन कविता सुनाकर कह रहे थे कि हमें तो अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे। अम्बेडकर नगर में एक हॉस्पिटल बनना था, उसका 400 करोड़ रूपया निकालकर दिल्ली में इनके मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को सब्सिडी में दे गये, लोक सभा चुनाव में गुमराह करने के लिए। हमने कोई मद नहीं काटी। इनकी सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स के अन्दर 600 करोड़ रूपया, जो एस.सी.,एस.टी. वेलफेयर का था, एस.सी.,एस.टी. हमारे नागरिक ऐसा कहते थे। उनकी सुविधा का पैसा निकालकर सब्सिडी के रूप में दे दिया। हमने अगर वह पैसा दिया सब्सिडी के रूप में ...(व्यवधान) सर, प्लीज़, यह दर्द है। मैं 15 साल उस विधान सभा में बैठा हूँ, मैंने दिल्ली की जनता का वह दर्द झेला है। हमने जो सब्सिडी दी है, 30 परसेंट का वायदा किया था। ये पढ़े-लिखे हैं, हुड्डा साहब के फादर भी चीफ मिनिस्टर हैं, ये अच्छे अंग्रेज़ी स्कूल से पढ़े हुए हैं। अगर ये उसका हिसाब निकालेंगे कि जो हमने 200 परसेंट तक और 400 परसेंट तक सब्सिडी दी है, वह 33 परसेंट बैठती है। हमने जो वायदा किया था, वह हमने करके दिखाया है। और हमने वह सब्सिडी किसी मद को काटकर नहीं दी है। हमने केन्द्र सरकार से डायरैक्ट पैसा लेने के बाद दिल्ली सरकार का जो 39 हज़ार करोड़ का बजट था, उसमें बाहर से सब्सिडी दी है।

महोदय, एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा कि अच्छे दिन की स्थिति क्या है। ...(व्यवधान) मैं एक किस्सा ज़रूर सुनाऊँगा। एक बार एक जंगल में नदी के किनारे एक बाग था। उस बाग में बहुत बंदर थे। जब बाग में बंदर हो गए तो बाग का माली परेशान हो गया। जब वह परेशान हो गया तो उसने बाग को बेच दिया। बाग बिक गए और दूसरी पार्टी ने खरीद लिये। उन्होंने बाग को कटवाना शुरू करवा दिया। बंदर बेचारे बड़े परेशान हो गए। बंदर कहने लगे कि बाग कट जाएगा तो हम क्या करेंगे। बंदरों ने शाम को मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि हम अपना एक बाग लगा देते हैं। उन्होंने बीज लिये और नदी के किनारे बीज लगाने शुरू कर दिये। सुबह बंदर गए तो उस बीज को खोद लिया और कहा कि यहाँ तो पेड़ निकला ही नहीं। उसके बाद अगले दिन फिर उन्होंने वह बीज बो दिया, फिर अगले दिन खोदकर देखा तो पेड़ नहीं निकला। सर, इनकी भी वही बंदर वाली स्थिति है। सरकार को बने अभी एक महीना भी नहीं हुआ और शोर मचाते हैं कि अच्छे दिन नहीं आए। अगर शादी करके भी लाए होंगे ...(व्यवधान) आपने देखा होगा कि एक महिला के लिए सबसे खुशी का दिन कौन सा होता है, जिस दिन उसके बेटे की शादी होती है, शहनाई बजती है। सर, वह माँ भी अगर अगले दिन अपने घर में खुशी देखना चाहती है तो पोते का इंतज़ार करती है और तब जाकर उसको महसूस होता है कि मेरे बेटे की शादी हुई थी। यहाँ फाइनैन्स मिनिस्टर चिदम्बरम जी नहीं हैं। अगर वे होते तो बहुत अच्छा लगता। 23 अक्तूबर, 2008 को उन्होंने एक ग्रूंट पर भाषण दिया था। मैं उस दिन टीवी पर देख रहा था और मैं उस समय असैम्बली का मैम्बर था। यह चिदम्बरम साहब का 21 अक्तूबर 2008 का भाषण है। उन्होंने कहा कि हमने जब आपको 1998 में इकोनॉमी दी थी तो वह बहुत डैट इकोनॉमी थी, और तुमने हमें 2004 में जो इकोनॉमी दी, वह बहुत बढ़िया दी है। इसलिए आप चिन्ता न करें, यह चिदम्बरम जी का बयान है। हमने एनडीए के टाइम में इनको बढ़िया इकोनॉमी दी और जो 2004 में हमने इनको बढ़िया इकोनॉमी दी, उन्होंने कहा कि तुमने हमको बहुत बढ़िया इकोनॉमी दी है, अब तुम ज़िन्दगी भर लौटकर आने वाले नहीं हो। यह कहा था उन्होंने लीडरशिप के बारे में। लेकिन परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, देश की सवा सौ करोड़ जनता के आशीर्वाद से हम तो यहाँ बैठे हैं लेकिन माननीय चिदम्बरम साहब नज़र नहीं आ रहे हैं। जिन्होंने अहंकार की बात कही थी, आज हमें अहंकार की बात बताते हैं, हमारे लिए कहते हैं कि तुम अहंकार में बोल रहे हो। उन चिदम्बरम साहब की भाषा क्या थी? आज हम पावर में आ गए। अभी मेरे मित्र ने कहा था ...(व्यवधान) आपने अपोलोजाइज़ किया है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री निनोंग ईरिंग। बिधूड़ी जी, आप प्लीज़ बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे दिल्ली के बजट के बारे में बोलने का अवसर दिया। हमारे इनीशियेटर हुड्डा साहब ने भी बोला कि यह हरियाणा या दिल्ली की बात नहीं है। दिल्ली हम सबकी है, दिल्ली दिल वालों के लिए है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

श्री निनोंग इरिंग : हम सबको देश की राजधानी दिल्ली से उतना ही प्रेम है जितना आपको है। हमारे जितने वक्तव्य हैं, हमने देखा है कि यहाँ सदस्य काफी उत्तेजित हो रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यह विडम्बना है जो उन्होंने कहा कि यहाँ चुनावी भाषण हो रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ आरोप-प्रत्यारोप नहीं करके हम दिल्ली के विकास के बारे में बात करें। आंकड़ों की बात हम नहीं कहेंगे। उत्तर-पूर्वी राज्यों से या दक्षिण से लोग आते हैं, या दूरदराज से दिल्ली को देखने के लिए लोग आते हैं। हम से पहले जो वक्ता बोले हैं, वह हम से बहुत छोटे हैं। मैं उस दिल्ली की बात कर रहा हूं जो वर्ष 1962 की थी, उस समय मेरे पिताजी सांसद थे और उसी समय मैंने दिल में एक भावना रखी कि मुझे यहां आना ही है। मुझे गर्व है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने 36 हजार 760 करोड़ रुपये का बजट रखा है उसमें उन्होंने कहा कि टैक्स इम्पोजिशन नहीं होता है। यह एक प्रावधान है, एक ट्रेडिशन है कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है, I stand to be corrected, तो बजट में किसी टैक्स का प्रावधान नहीं होता है। खास तौर से बिजली के बारे में एक बहस चल रही है कि 30 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान था। हमारी पिछली कांग्रेस की शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उन्होंने दो रुपये की सब्सिडी दी थी, जबकि इस बार 1 रुपये 80 पैसे की सब्सिडी रखी गयी है। इसमें नया क्या है, यह मुझे समझ में नही आया है। लेकिन इस बारे में मैं बहस नहीं करना चाहता हूं। लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि बवाना पावर प्लांट को गैस सप्लायी है, इसके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया है? सीवरेज के लिए आपने 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस बारे में हम यही चाहते हैं कि जो पहले के अंडर यूटीलाइज़ और पहले के पैंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनको पहले पूरा क्यों नहीं करते हैं? स्कूल्स के बारे में वर्ष 2013-14 के लिए 100 स्कूल्स खोलने का प्रावधान रखा गया था, लेकिन आपने केवल 20 नये स्कूल्स खोलने का प्रावधान रखा है। हॉस्पीटल्स के बारे में आपने कहा कि रोहिणी में सुपर स्पेशयलिटी हॉस्पीटल खोलेंगे और 50 डायलिसिस सेंटर्स खोलेंगे। यह सब अच्छी बात है और हम भी उसको सपोर्ट करते हैं। डॉ. हर्ष वर्द्धन जो कि भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और दिल्ली में पहले विधायक भी रह चुके हैं, उन्हें इसकी जानकारी भी है कि दिल्ली में कोलेरा, टाइफोइड बढ़ रहा है, इसके लिए आपने क्या प्रावधान किए हैं? वह इस बजट में दिखायी नहीं दिया है।

महोदय, महिलाओं के साथ एट्रोसिटिज़ और हैरसमेंट्स हो रहे हैं। जेएनयू की स्टडी में भी आया है कि हर रोज़ सौ में से एक महिला के साथ सेक्सुअल हैरसमेंट हो रहा है। इसके लिए आपने कोई प्रावधान नहीं किया है। हमारे उत्तर-पूर्वी राज्यों के तीन-चार लाख लोग दिल्ली में रहते हैं, चाहे वह सरकारी नौकरी करने वाले हैं, चाहे वे छात्र हैं या वर्किंग विमन हैं, सब यहां रहते हैं। हमारी सरकार में मंत्री श्री घटोवार ने पिछली बार वहां के लोगों के लिए एक हॉस्टल का प्रावधान रखा था। इस बार चुनाव के दौरान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब वहां गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम लोग उत्तर-पूर्वी राज्यों खास तौर से वर्किंग विमन के लिए और पढ़ने वाले बच्चों को कोई शिकायत नहीं होने देंगे। उस बात का इस बजट में कहीं जिक्र नहीं है। इस बारे में भी आपको देखना होगा। ग्लासगो में कॉमन वेल्थ गेम्स हो रहे हैं, उसमें संजिता चुमकचोम और मीराबाई साइकोम है, मेरीकोम थी, बाईचुंग भूटिया है। यह सब वहीं के लोग हैं। हम सब एक हैं। दिल्ली हमारा भी है, सिर्फ आपका नहीं है। दिल्ली दिल वालों के लिए है और हम सब दिल वाले हैं, खास तौर से उत्तर-पूर्वी राज्य के लोग। मैं यही कहना चाहता हूं when there is an action, there is always a reaction. शायद हमारे यहां से भी कोई गुस्ताखी हुई होगी, हमारी भी कुछ गलतियां होंगी, लेकिन उन सभी को छोड़ कर, दिल्ली को कैसे आगे बढ़ाएं, उसको एक अच्छी सिटी कैसे बनाएं?इसे वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बनाएं, इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। खासतौर से, अभी जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, बेज़रुआ कमेटी की जो रिपोर्ट आयी है, उसे देखते हुए भी हमारी सरकार को एक ऑफिस रखना चाहिए ताकि उत्तर-पूर्व से जो लोग आते हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए। सिर्फ़ उत्तर-पूर्व से ही नहीं, वे चाहे साउथ से आएं, चाहे नॉर्थ से हों, चाहे वेस्ट के हों, हमें सभी को देखना है।

महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपका आभारी हूं कि आपने हमें इतने कम समय में बोलने का मौका दिया। हमारी पार्टी की ओर से जो अन्य माननीय सदस्य ने कहा है और हुडा साहब ने जो कहा है, मैं उनका समर्थन करता हूं। दिल्ली का जो बजट है, हम भी चाहते हैं कि वह अच्छे-से पारित हो। लेकिन इसमें हम ने जो प्रावधान रखा है, उसका भी आप ध्यान रखें। जितने लोग भी यहां हैं, चाहे वे तमिलनाडु से आए हों, केरल से आए हों, राजस्थान से आए हों, जम्मू-कश्मीर से आए हों या नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट से आए हैं, हम सब दिल्ली वाले हैं।

HON. CHAIRPERSON : Shri Maheish Girri.

...(*Interruptions*)

SHRI RAJEEV SATAV (HINGOLI): Sir, I am on point of order.

HON. CHAIRPERSON: Under what rule are you raising your point of order?

SHRI RAJEEV SATAV : It is under Rule 349 (xvii) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. It says that the Member shall not leave the House immediately after delivering his speech. But here, the hon. Member ha left the House immediately after delivering his speech. उन्हें कुछ-न-कुछ तो बता दीजिए। This is the rule...(*Interruptions*) He left the House immediately after delivering his speech. उन्हें ऐसा बता दीजिए।

HON. CHAIRPERSON: It is okay.

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : सम्माननीय महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं पहली बार इस संसदीय परिसर में आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर में प्रथम बार आया हूं और प्रथम बार बोल रहा हूं।

महोदय, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे यहां पहली बार खड़े होकर बोलने का यह जो सम्मान मिल रहा है, यदि किसी को इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है तो वह मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली के जितने वोटर्स हैं, उन सभी को जाता है जिन्होंने मेरे प्रति भरोसा रखा है। आज उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम यहां पर हैं, हम उनके लिए हैं। मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं उसी बच्चे की तरह अनुभव कर रहा हूं जो मां के गर्भ से पहली बार इस सृष्टि को देखता है और प्रथम बार बोलता है। यह बिल्कुल वैसा ही अनुभव है। चुनावी प्रक्रिया के गर्भ से जन्म लेकर संसद सदस्य के रूप में आज यहां पर प्रथम बार बोल रहा हूं। बिल्कुल उसी बच्चे की तरह मेरा अनुभव है। यदि मेरे शब्दों में कहीं कोई आगे-पीछे हो जाए तो मुझे माफ़ कर दिया जाए।

महोदय, मैं पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के लोगों की जो पीड़ा हैं, अधूरे सपने हैं, उनके जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी मांग रखने के लिए आया हूं। मैं इस क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र बनाना चाहता हूं। मैं पूर्वी दिल्ली क्षेत्र को अपूर्व दिल्ली बनाना चाहता हूं जिसके अधिकारों के लिए मैं आज यहां पर खड़ा हूं।

महोदय, आज मैं दिल्ली के बजट पर बोलने वाला हूं। उस बजट तक पहुंचने के लिए मुझे थोड़ी-सी भूमिका बनानी होगी। वह यह है कि यदि विश्व के इतिहास में सदियों पहले हम भारत को देखते हैं तो वह विश्व गुरू की भूमिका निभाता था। वह आध्यात्म से लेकर अंतरिक्ष तक, ज्ञान या विज्ञान के क्षेत्र में या विश्व भर में कुछ भी हो, उसमें केन्द्रीय भूमिका निभाता था। चाहे वह शासन हो, शिक्षा हो, व्यापार हो या अर्थतंत्र हो, हर क्षेत्र में हम निपुण हुआ करते थे क्योंकि इस राष्ट्र की नीतियां इन विषयों को बल प्रदान करतीं थीं। ये वह नीतियां थीं जिस ने राष्ट्र को विश्व गुरू के पद पर पहुंचायी। यदि यह राष्ट्र अर्थतंत्र में मजबूत था, वह सोने की चिड़िया कहा जाता था तो वह इस राष्ट्र की नीतियों के कारण कहा जाता था क्योंकि वह उसे बल प्रदान करती थीं। अगर विश्व की कक्षा में यह देश आज पीछे रह जाता है तो वह नीतियों के कारण ही होता है।

सभापति महोदय, यह देश अच्छे दिनों की ओर उसी दिन चल पड़ा था जब इस देश के सर्व सम्माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस लोकतंत्र के मंदिर में अपना माथा नवा दिया था। जब एक

राष्ट्रपुरुष माथा नवा कर राष्ट्र पूजा का संकल्प लेता है तो वह अपने राष्ट्र के भविष्य को सुनिश्चित करता है कि उसे किस दिशा में लेकर जाना है, अच्छे दिनों की ओर लेकर जाना है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। मैं जब भी अपने युवा अवस्था से अभी तक के काल में लोक सभा टी.वी., राज्य सभा टी.वी. देखता था तो कुछ स्पीकर थे, जो बोलते थे, आकर्षण का केन्द्र हुआ करते थे। लोक सभा टी.वी. देखता था, सुषमा स्वराज जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्तव्यों को देखता था। जब राज्य सभा टी.वी. आता था, तो विशेषकर अरुण जेटली जी के वक्तव्य को देखता था। कई बार मैंने ऐसा मौका देखा, कुशलता से अपने वक्तव्य से उन्होंने किस तरह से अपनी बातों को रखा। आज उसी बजट पर मुझे उनके समर्थन में बोलने का मौका मिला है, यह मैं अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात मानता हूं।

सभापति महोदय, इस दिल्ली की भारत में एक अलग पहचान भी है। यह दिल्ली अपना श्वास, अपनी उड़ान भरना चाहती है। इस उड़ान को यदि पंख देने का काम किसी ने किया है तो हमारे माननीय वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली जी ने किया है। कई वर्षों से कुंठित सपनों को यह दिल्ली पूरा करना चाहती है। इन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने जो बजट पेश किया, उसकी सीधी-सीधी निन्दा नहीं हुई, बार-बार केवल इतना ही कहा गया कि अगर इलैक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में या विपक्षी दलों का सुर देखें, तो यही था कि यह चुनावी बजट है, चुनावी बजट है, चुनावी बजट है।

सभापति महोदय, अभी-अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कई सारी बातें कहीं। रमेश विधूड़ी जी ने कहा कि हमने तो अपने मेनिफेस्टों में जो कहा था, वह हमने किया है। कई बार आपने चुनावी बजट किया, जो वायदे आप पूरे नहीं कर पाए, हमने जो जनता को वायदे किए हैं, वे पूरे करने हैं, क्योंकि हमारी पार्टी उस संस्कृति से आती है - "प्राण जाए, पर वचन न जाए।" वह पूरा करने के लिए हमने इस बजट को पेश किया है। "सब का साथ, सब का विकास," इस बजट में यह भावना भी झलकती है। जैसे हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था, गरीबों, वंचितों, पीड़ितों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, युवाओं के लिए, व्यापार और रोजगार के लिए, सब को बढ़ावा देने वाला यह बजट है। इसके मुख्य बिन्दू पर मैं जाता हूं तो यमुना, जो इस देश की राष्ट्रीय धरोहर है। इस यमुना के ऊपर कई पैसे खर्चे हुए हैं। मैंने स्वयं एक आंदोलन चलाया था - "मेरी दिल्ली, मेरी यमुना।" इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। अखबारों में भी कई बार इसके बारे में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया, यह तो डर्टी ड्रेन है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि इसके लिए कई बजट में प्रावधान किया गया, परन्तु यमुना वैसी की वैसी है। आज हमारे प्रधान मंत्री जी ने गंगा और यमुना के लिए एक अलग मंत्रालय खड़ा किया, क्योंकि हमारे संस्कार इस संस्कृति का सम्मान करते हैं, उसे पता है राष्ट्रीय सम्पति और राष्ट्रीय धरोहर क्या होती है। वार मेमोरियल के लिए यहां पर बजट में प्रावधान रखा गया, क्योंकि आज अगर हम यहां पर खड़े हैं, यह देश अगर स्वतंत्र श्वास भर रहा है तो हमारे शहीदों की वजह से, उनके सम्मान में यहां पर वार मेमोरियल भी बनाया जाएगा। यह देश माता-पिता के सम्मान और संस्कारों से पलता है और वह सम्मान एवं संस्कार तभी दिया जाता है, जब हम उनके लिए कुछ करते हैं। वृद्धों की पेंशन,जो उनके जीवन का अधिकार और आधार है, वह बंद करवा दी गई थी, जिसको हमारी इस गवर्नमेंट ने इस बजट में उन वृद्धों की पेंशन की फिर से शुरुआत की गई। यह एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया। झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती के कई लोग आज भी बाहर शौच के लिए जाते हैं, उनके लिए शौचलयों की व्यवस्था, पेयजल और सीवर के लिए मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बात रखी है, इसलिए मैं ज्यादा लम्बा उसमें नहीं जाऊंगा, परन्तु पेयजल और सीवर के लिए दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अभी-अभी हमारे भाई प्रवेश जी ने कहा था, एक आशा किरण की, जो संस्था की बात कही, जिसमें 350 बच्चे हम रख सकते हैं। जिन्हें हम मानसिक रूप से असंतुलित कह सकते हैं, जिसमें नौ सौ बच्चे हैं। पिछली सरकारों को मानसिक केन्द्र, जहां पर ये ठीक हो सकते हैं, ऐसे मानसिक अस्पतालों को खोलना था, उनको बढ़ाने की बजाए इन सरकारों की नीतियों ने मानसिक रोगी बहुत बढ़ा दिए।

सभापति महोदय, मैं स्कूलों की बात करूं तो बीस नये स्कूलों की बात यहां पर आती है। यहां पर हमारे मित्र कह रहे थे कि आप बीस ही स्कूल खोल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं? इतने सालों में दिल्ली के अंदर एक कॉलेज तक नहीं खुला। पूर्वी दिल्ली सबसे आबादी वाला क्षेत्र है, जहां सबसे ज्यादा युवा हैं।

16.00 hrs.

मुझे बहुत खेद है कि ऐसे क्षेत्र में 65 वर्षों से एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए हमारे यहां के बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी वहां पर हमें दी, उसके लिए एक अलग से बजट हमें दिया। लेडीज़ हॉस्टल भी वहां पर दिया गया है, पूर्वी दिल्ली की जनता उसके लिए उनका धन्यवाद भी करती है।

इसके साथ ही हमारी पूर्वी दिल्ली के लिए थोड़ी बहुत जो मांगें हैं, वे ये हैं कि पूर्वी दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है, जहां क्राइम रेट बहुत हाई है। वहां पर क्राइम रेट हाई है, क्योंकि, वहां पर बहुत बदहाली है और जितनी वहां की जनसंख्या है, उतनी संख्या के सामने पुलिस बल कम है। मैं वित्त मंत्री को प्रार्थना करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में भी वे थोड़ी सी मदद करें, ताकि हम क्राइम रेट को नीचे लेकर के आयें और हमारी माताओं-बहनों की रक्षा-सुरक्षा कर पायें।...(व्यवधान) मैं बस दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

वहां पर रोज़गार बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे जो व्यवसाय चलाने वाले हैं, गांधीनगर एक क्षेत्र आता है, जहां पर इन्हीं की सरकार के एक एम.एल.ए. हैं, वहां पर बार-बार आये दिन सीलिंग होती रहती है। इससे वहां के छोटे-छोटे व्यापार बन्द हो रहे हैं, अगर वहां पर व्यापार ही बन्द हो गये तो वह क्षेत्र कैसे विकास कर पाएगा, वहां के युवाओं को रोज़गार कैसे मिलेगा, इसलिए उस क्षेत्र की ओर भी मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं।

वहां पर मयूर विहार के क्षेत्र में एक संजय झील है, जो बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। मैं अपनी सरकार को प्रार्थना करता हूं कि उसके विकास के लिए केन्द्र से कुछ अनुदान मिले। केन्द्र सरकार के साथ हम वहां काम करना चाहेंगे।

अन्त में यह बात मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली सौ कदम आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन पिछले 15 साल की सरकार और 50 दिन की सरकारों ने इसको 50-100 कदम और पीछे धकेल दिया। अब हमें 150-200 कदम आगे बढ़ाने हैं। आप हमारी आलोचना करते हैं, हम आपकी आलोचना का सम्मान भी करते हैं, पर आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपकी आलोचना शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में क्यों है, हमें तो दो ही महीने हुए हैं, इन 15 सालों में आपने किया क्या? हमने कम से कम कदम तो उठाया है। हमने 20 स्कूलों के लिए कदम उठाया है, 500 करोड़ रुपये बिजली के लिए हमने कदम उठाया है, 200 करोड़ का पानी के लिए कदम उठाया है। चाहे हजारों किलोमीटर की विकास की यात्रा ही क्यों न हो, उसकी पहले कदम से ही शुरूआत होती है और वह कदम हम बढ़ा चुके हैं और यह कह सकते हैं कि अब दिल्ली मुस्कुराएगी। वह कदम हम बढ़ा चुके हैं, अगर आप वह कदम नहीं बढ़ा पाये तो इसमें हमारा दोष नहीं है। अगर पप्पू पास नहीं होता है तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है।

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं दिल्ली के बजट के विरोध में आम आदमी पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हूं।

16.03 hrs.

(Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair)*

मैं सबसे पहले कांग्रेस से शुरू करूंगा। दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस पिछले 15 साल से सक्रिय है, खैर, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। 15 साल से कांग्रेस सक्रिय थी, अब तो कांग्रेस की दिल्ली में अपने बजट की बात न ही करे तो अच्छा है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, न ही पब्लिक को, न ही सरकार को।...(व्यवधान) एक जमाना था जब दिल्ली में 15 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, अब तो जमाना यह है कि मां भी दिल्ली में अपने बच्चे को कहानी सुना सकती है कि एक थी कांग्रेस।

हुड्डा साहब बोल रहे थे कि इसका हश्र हो जायेगा, उसका हश्र हो जायेगा, कांग्रेस वाले पहले अपने एम.एल.ए. गिन लें, यहां पर कितने हैं। लालू जी के बच्चे ज्यादा हैं, इनके एम.एल.ए. कम हैं। मेरे ख्याल में ये दूसरों को हश्र बताने के बजाय अपनी पीढ़ी के नीचे अपने घर में खुद देख लें। हमारी आम आदमी पार्टी सिर्फ 49 दिन दिल्ली में सत्ता में रही है और ये 15 साल रहे। उससे पहले साहिब सिंह वर्मा और बी.जे.पी. की सरकार भी दिल्ली में रही है। शीला दीक्षित जी का लग रहा था, जो बजट जेटली साहब पढ़ रहे थे कि यह शीला जी का लिखा हुआ जेटली साहब पढ़ रहे हैं। यह बिल्कुल सेम बजट है। वही पुरानी बात, जिसकी अभी बहस चल रही है। तीस परसेंट बिजली के दाम कम करने वाले बी.जे.पी. वालों के पोस्टर अभी भी दिल्ली में फटे-पुराने लगे पड़े हैं। उसके बाद एक और मैनीफैस्टो आ गया, 30 परसेंट बिजली के दाम कम करने के दो मैनीफैस्टो आ गये, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो आम आदमी पार्टी ने सब्सिडी दी थी, वह भी खत्म कर दी। उसके बाद दो बार बिजली के रेट बढ़ा दिए और उसके बाद 260 करोड़ रूपए का लॉलीपाप थमा दिए। यह कहा कि अब हमने कम कर दिया। बड़े हिसाब-किताब लगा के कहा कि एक रूपए बीस पैसे दिए, तैंतीस परसेंट बनता है। * भी पता नहीं कैसे कर रहे थे? इनका हिसाब-किताब पता नहीं कैसा है? मैं इनसे पहले ही पूछ चुका हूं कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं? ...(व्यवधान) मुझे समझ नहीं आता सभापति जी, ये साठ महीने की बातें करके कि हमें साठ महीने दो। ...(व्यवधान) ये बातें करते हैं 2022 की। ...(व्यवधान) अगर साठ महीने दे दिए जाएं तो वह वर्ष 2019 में खत्म हो जाते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : किसी माननीय सदस्य का नाम लेकर कोई आरोप नहीं लगाया जाता है।

â€¦(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : मैं माननीय सदस्य का नाम ले रहा हूं। इन्होंने आंकड़े दिए हैं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कार्यवाही में से नाम निकाल दिया जाएगा।

â€¦(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : इनको शौक है सीधा यहां आने का और फिर मांगने का क्या फायदा हुआ, माफी मांगने का शौक है माफी मांग लेंगे। ये दो-तीन बार जिस दिन माफी न मांगे, इनका संसद में आना बिल्कुल सही नहीं होता। ...(व्यवधान) सभापति जी, मुझे बोलने दीजिए। ...(व्यवधान) उनको इसके लिए बोल दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका नाम नहीं जाएगा।

श्री भगवंत मान : इनका नाम माननीय *है। माननीय * जो कि पहले भी माफी मांग चुके हैं।

बिजली कंपनियों का हमने 48 ऑवर्स में कैग ऑडिट करवाया। अरविंद केजरीवाल जी की जब सरकार बनी तो विद इन 48 ऑवर्स हमने कैग ऑडिट के आर्डर दे दिए। उसके बाद क्या हुआ? कंपनियां अभी तक किताबें नहीं दे रही हैं। अभी तक किताबें नहीं दीं, सेंटर में भी ये हैं, एमसीडी में भी ये हैं, सात इनके विधायक भी हैं, तो अभी कंपनियों को क्यों ये नहीं कहते कि ऑडिट करवाने के लिए हमें किताबें दो, ताकि बिजली कंपनियों की कैग की तरफ से ऑडिट हो सके।

इन्होंने कहा कि हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। इनके कई सांसद कहते हैं कि कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया। सभापति जी, ये टैक्स बढ़ा ही नहीं सकते हैं। एकार्डिंग टू आर्टिकल 356 और 265, ये टैक्स बढ़ा ही नही सकते, ये तो सिर्फ लागू कर सकते हैं। ये बढ़ा के तो दिखायें। ये खुद ही अपने आप क्रेडिट लेने लगते हैं। ...(व्यवधान)

इन्होंने बातें कही थीं कि स्पोर्ट्स में स्कॉलरशिप लाएंगे, इस बजट में कोई बात नहीं की गयी। ये मैनिफैस्टो की बातें हैं। आईएएस और आईएफएस की एकैडमी खोली जाएगी, इसकी कोई बात नहीं है। पचास हजार नई जॉब्स, पूरे देश से लोग दिल्ली में रोजगार की तलाश में आते हैं, लेकिन जॉब्स के बारे कुछ नहीं बोला गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से किसानों को छः परसेंट जो अनाज बेचने का टैक्स लगता है, वह हमने माफ किया था, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला। दिल्ली में एंबैसीज हैं, फॅरिन एंबैसीज हैं, खासतौर से नार्थ-इंडियंस, खास तौर से पंजाबीज यहां बड़ी संख्या अपनी फेमिली के साथ वीजा लेने के लिए आते हैं। वहां बैठने के लिए, पानी पीने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। भेड़-बकरियों की तरह पुलिस वाले उनको भगा देते हैं, वे फिर पीछे चले जाते हैं। उनके लिए खाने-पीने का, क्योंकि बच्चे-बुजुर्ग भी वहां होते हैं, उनके लिए बैठने के प्रबंध के बारे में सोचने तक का इनके पास टाइम नहीं है। जगत गुरू गुरूनानक देव जी ने गुरूवाणी में लिखा है कि पवन गुरू पानी पिता माता धर्त महत, उन्होंने पवन को, हवा को गुरू का दर्जा दिया, पानी को पिता का और धरती को माता का, जो पिता का दर्जा पानी का है, दिल्ली सबसे ज्यादा इससे पीड़ित है। दिल्ली में पानी की समस्या है, बड़े-बड़े माफिया बन चुके हैं, जब आम आदमी पार्टी की सरकार आयी थी, हमने 20 हजार लीटर पानी पर मंथ हर घर के लिए फ्री कर दिया था। जो टैंकर माफिया था, वह उस समय बहुत हद तक कम हो गये थे। इन्होंने वह सब्सिडी भी खत्म कर दी, फिर पानी के टैंकर माफिया सक्रिय हो गये। इनके पास इस बजट में देने के लिए कुछ नहीं है। ...(व्यवधान)...

महोदय, आखिर में मैं चार लाइनें कविता की बोलूंगा क्योंकि हमारे पास तो टाइम कम होता है और कविता ही एक ऐसा हथियार है, जिससे हम बहुत बड़ी बातें कम समय में कह सकते हैं। मैं तो घंटी का बहुत सत्कार करता हूं। आप इनको समझा दीजिए, ये घंटे का भी सत्कार नहीं करते और दो-तीन घंटे बोलते रहते हैं। मेरी कविता यह है, यह दिल्ली कह रही है " कभी टमाटर ने कभी प्याज ने, दिल्ली खा ली है कांग्रेस और बीजेपी के राज में, महंगाई की मार से दुखी आम आदमी, ऑटो रिक्शे और स्कूटर वाले, लेकिन बात ही नहीं सुनते लाल बत्ती और हूटर वाले। "

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले सुनते थे कि दिल्ली बड़े दिल वालों की है, लेकिन आज पता चला बजट देखकर कि दिल्ली बड़े बिल वालों की है। यहां बिल बड़े आते हैं, दिल उससे बहुत डरते हैं तो दिल वालों की दिल्ली को बचाने के लिए इसे बिल वालों की दिल्ली न बनायें। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहता हूं कि इन बातों पर ध्यान देकर, अगर दिल्ली की बजट में हमारी भी कोई भूमिका हो सकती है, तो उस को हम देने के लिए तैयार है।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : माननीय सभापति महोदय, मैं दिल्ली की बजट पर बोलने जा रहा हूं। मैं नार्थ-वेस्ट, दिल्ली से चुन कर आया हूं। मैं वहां के लोगों का धन्यवाद करता हूं। अगर, दिल्ली में सबसे पिछड़ा क्षेत्र कोई है, तो वह उत्तर-पश्चिम दिल्ली है, जहां से मैं चुन कर आया हूं। वहां पर मेट्रो नहीं है, जबकि मेट्रो फरीदाबाद और गुड़गांव तक पहुंच चुकी है। हमारे साथी स्लिडिंग बाय लाज की समस्या के बारे में कहने ही वाले थे, शायद वह नहीं कह पाए। गांवों में स्लिडिंग बाय लाज लागू करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनके पहले मैं बजट पर थोड़ा बोलना चाहता हूं। I would like to very briefly speak on its financial implications. हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने उन्हीं क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया है, जहां ज्यादा आवश्यकता है। पानी की समस्या है। He has not only paid full attention to it in the Delhi Budget, but in the General Budget also enough attention was paid by him and Rs. 5,000 was allocated for making water available to Delhiites. सबसे ज्यादा झुग्गी-झोपड़ियों में पानी की व्यवस्था करने की जरूरत है। One more significant feature of the Budget is that क्लस्टर्स में, झुग्गी-झोपड़ियों में टॉयलेट्स की बहुत बड़ी समस्या है। कम्युनिटी टॉयलेट्स सारे जे.जे. कॉलोनियों में लगेंगे। I would like to thank the hon. Finance Minister for this. 1380 लो-फ्लोर की बसें चलेंगी और 400 क्लस्टर बसें होंगी। पहले से 1200 बसें चलती थीं, अब 400 बसें और चलेंगी तो 1600 बसें हो जाएंगी। हालांकि यह रिक्वायरमेंट को मीट आउट नहीं करता है, फिर भी, मैं समझता हूं कि it is a forward-looking and quite a progressive step, given the situation. हम लोगों को जो इनहेरिटेन्स में मिला है, उसको हम लोग सडेनली क्योर नहीं कर सकते हैं, दिल्ली को दुनिया का सबसे सुन्दर शहर नहीं बना सकते हैं। This will take some time.

Of course, 20 new proposed schools is a welcome step. It depicts that willingness is there. I would like to thank the hon. Finance Minister for providing my North-West Delhi Constituency a medical college with super-speciality status.

मैं उनका बहुत आभारी हूं कि बहुत दिनों के बाद दिल्ली में एक मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। What was the pace of development during the Congress Government?

हमारे सामने के जो साथी हैं, वे खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि इतने सालों के बाद मेडिकल कॉलेज खुलने की बारी आई है, अगर ये रहते तो शायद इसकी बारी नहीं आ सकती थी। इन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 3702 करोड़ रुपए का बजट में एलोकेशन किया है। मेरा ख्याल है कि यह लुकींग फारवर्ड है और पिछले वर्ष से ज्यादा दिया गया है। मुनक से हैदरपुर तक पानी का जो चैनल बनना है, इसके लिए बजट में काफी कुछ किया गया है। There is a proposal to make *pucca* parallel channel from Munak to Haiderpur functional after resolving the issues with Haryana, and very soon we will be getting safe water for meeting the needs of nearly 35 lakh people. 35 लाख जो दिल्लीवासी हैं, हम उनकी नीड जल्दी पूरा करने जा रहे हैं।

इसके अलावा हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बल्कि पूरी दिल्ली की भी समस्या है। वहां ज्यादातर रूरल एरिया है। वहां के गांव वाले सोचते हैं कि दिल्ली सरकार या दिल्ली के इलिट रूरल बॉयज्ड हैं। इसलिए गांव पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह हमारी गलती नहीं है, प्रिविय्स सरकारों की गलती रही है। मैं इसके साथ सहमत भी हूं। गांव में इतनी बुरी हालत है कि अगर टैंकर से पानी न पहुंचे तो लोग पानी नहीं पी पाते। एक हफ्ते में एक बार टैंकर जाता है। वे उसी से अपना निर्वाह करते हैं।

मैं मैट्रो के बारे में जिक्र कर रहा था। मैट्रो फरीदाबाद, गुड़गांव और पलवल तक जा रही है। क्या मैट्रो नरेला तक नहीं जा सकती, कुतुबगढ़, बवाना तक नहीं जा सकती? This part is completely neglected. I would therefore suggest to the hon. Finance Minister to consider this demand of rural Delhi.

इसके अलावा लाल डोरा का क्षेत्र 35 साल पहले बढ़ा था। पापुलेशन मल्टीप्लाई हो गई है। They are really living in very bad conditions and in very congested houses. लाल डोरा के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाना चाहिए जो अभी तक नहीं बढ़ा है। पापुलेशन लगभग दुगुनी हो चुकी है।

इसी तरह किसानों की जो लैंड एक्वायर हुई है, उन्हें alternative plot in lieu of land acquired has not been given. मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह दिया जाना चाहिए। Builders or the contractors acquire huge tracts of land with the condition that houses would be provided to the Economically Weaker Sections (EWS) of the society. सारे बिल्डर्स की जांच की जानी चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन का पूरा गड़बड़ झाला है। गरीबों को नहीं दिया जाता। बड़े-बड़े बिल्डर्स हैं। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह करप्शन काफी समय से चल रहा है।

हमारे साथी रमेश बिधूड़ी जी सैक्शन 81 पर बोलना चाह रहे थे। सैक्शन 81 में दिया गया है कि अगर किसान तीन साल तक लैंड इस्तेमाल नहीं करता तो the Government takes it back. किसान ऐसी परिस्थिति में हैं कि वहां कल्टीवेशन नहीं कर सकते। उनकी लैंड जबरन छीन ली जाती है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा अन्याय है। इस सैक्शन में परिवर्तन होना चाहिए। There are really anguished. वे सोचते हैं कि हम भारत में रह रहे हैं, यहां संसद है, नई दिल्ली है, करोल बाग है। यह इंडिया है। उनके मन में जो भावना है, उसे भी दूर किया जा सकेगा। I propose one thing. दिल्ली के चारों तरफ एक रिंग रोड बननी चाहिए। It is concerned with the Government of India and the Ministry of Surface Transport because अगर दिल्ली के अंदर का लोड कम करना है, It is overcrowded. अगर आप कभी मयूर विहार, यमुना पार गए होंगे तो आपको एक, डेढ़ घंटा लगा होगा। मीटिंग में देर से पहुंचे होंगे। मैं समझता हूं कि इसका सौल्यूशन यही है कि दिल्ली की पेरीफरी में एक रिंग रोड बनना चाहिए। I find that as the only solution. Otherwise, there is no alternative. I will conclude very soon.

लगभग 800 कालोनीज़ रैगुलराइज नहीं हैं। The High Court had given a very clear-cut verdict that even though the colonies have not been regularized, basic amenities should be provided in those colonies. बेसिक एमीनिटीज में पानी, सीवर, रोड आती है। वह भी नहीं दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी को इतने साल बीत गए, अगर जन्म लेने का अधिकार है तो क्या लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। रोज घर तोड़े जाते हैं। चोरी से घर बनाए जाते हैं, एमसीडी वाले पैसे लेते हैं, पुलिस भी उसमें मिली हुई है, कारपोरेटर मिले हुए हैं, नेता मिले हुए हैं। यह सिस्टम चला आ रहा है। जो बाहर से लोग आकर यहां काम करते हैं, where should they live, अगर उनको बच्चा पैदा करने का अधिकार है और सरकार उनका वह अधिकार नहीं छीनती है, तो उन्हें रहने के लिए कम से कम दो गज जमीन का अधिकार तो मिलना चाहिए। यह विरासत हमारे सामने के साथियों ने छोडी है। यह देखकर हमें बहुत तकलीफ होती है कि हम आजाद भारत में रह रहे हैं या नहीं।

आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी के कई काम छूट गये हैं। जैसे घेवरा में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स है। उस पर काम किया जाना चाहिए। वहां एक सौ एकड़ से ज्यादा जमीन एक्वायर हो चुकी है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। मैं एक बात स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के बारे में कहना चाहता हूं। जब दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, उस समय उन्होंने शैडयूल्ड कास्ट्स के डेवलपमैंट का 744 करोड़ रुपया कामनवेल्थ गेम्स में डायवर्ट कर दिया था। अब यह शैडयूल्ड कास्ट्स और दिल्ली के डेवलपमैंट के बारे में क्या कह सकते हैं, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है।

महोदय, मेरे एरिया में there is abandoned land. I request the Central Government कि वहां फॉरेन इन्वेस्टमैंट का काफी स्कोप है। DDA has acquired a vast tract of land but that land is lying vacant. यह देखकर बड़ा दुख होता है कि माइल्स एंड माइल्स जमीनें खाली हैं। वे न किसानों के पास हैं और न ही सरकार के पास हैं और वह कुछ कर नहीं पा रही हैं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : उदित राज जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. उदित राज : मैं भगवंत मान जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। ...(व्यवधान) *मेरे जूनियर रहे हैं। वे भी आईआरएस थे और मैं भी आईआरएस था। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप किसी का नाम मत लीजिए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप किसी का नाम लेकर चर्चा मत कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. उदित राज : उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि बिजली कम्पनियां 50 प्रतिशत भ्रष्टाचार करती हैं, लेकिन जब सत्ता में आये तब इन्हें देखने को मिला कि 80 परसेंट बिजली कम्पनियों की खरीद का ही दाम था। उस तरह से ये असत्य बोलकर सत्ता में आये और पूरा नही कर पाये कि बिजली कम्पनियां 50 परसेंट भ्रष्टाचार कर पायी हैं। अब ये क्या बोल सकते हैं?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

माननीय सभापति : अगर किसी का नाम कार्यवाही में आया है, तो उसे हटा दीजिए।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति महोदय, अच्छे दिन के बजट के बारे में, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि आजादी के बाद दिल्ली की जिंदगी और गति को उत्तर पूर्वी भारत के लोगों ने अपने खून-पसीने से, अपनी मेहनत से संवारा और सींचा है। यदि वे मेहनत न करें, तो दिल्ली में रहने वाले लोग, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी है, वह छीन जायेगी। मैं समझता हूं कि दिल्ली के कारपोरेट, माफिया, नेता और पुलिस, इन चारों के गठबंधन को यदि जोड़ दिया जाये, तो दिल्ली को किसी ने लूटा है, दिल्ली को किसी ने तंग किया है, दिल्ली की जिंदगी और गति को किसी ने छीना है, दिल्ली के आम और गरीब लोगों की खुशी और मुस्कुराहट को किसी ने छीना है, तो इन चारों के गठबंधन ने लूटा है। इन चारों के गठबंधन ने मिलकर जितना गरीबों का शोषण किया है, शायद इस देश में किसी ने उतना शोषण नहीं किया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन दो महीनों में जो आंकड़ा दो दिन पूर्व आया है, उसे आप देखें। निर्भया रेप कांड के चलते पूरे देश में हंगामा हुआ था, उस रेप के बाद 35 प्रतिशत रेप में बढ़ोतरी हुई है। अभी कुछ दिन पहले चार गैंगरेप हुए हैं। हाय-तौबा मचाने वालों और अच्छे दिन कहने वालों को क्या रेप केसेज याद नहीं

आते?

उत्तर-पूर्वी भारत ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ जो बच्चे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, वे कितनी बदतर जिंदगी जीते हैं। उनके साथ दिल्ली के ठेकेदारों, दिल्ली के लॉज़ माफियाओं, घर माफियाओं द्वारा किस तरह का बर्ताव किया जाता है, कभी उस पर इनकी चिन्ता नहीं रही है। आज यूपीएससी के छात्रों से लेकर, यदि हमेशा सबसे ज्यादा कोई दिल्ली में पीटे गये हैं, तो वे ठेले वाले हैं। जो सब्जी बेचता है, जो फल बेचता है, जो दिल्ली के घरों तक उनकी खुशी को पहुंचाता है, यदि सबसे ज्यादा शोषण हुआ है, तो उन गरीबों का हुआ है और उनके लिए इनके बजट में कुछ नहीं है। दूसरा, सबसे ज्यादा यदि किसी का शोषण हुआ है, तो वे दिल्ली में बाहर से आकर रहने वाले छात्र हैं, जिनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिनके रहने के लिए, जिनके पानी के लिए, जिनकी जिंदगी को गति देने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह इनके बजट में नहीं है। मैं आदरणीय विद्वान वित्त मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि जो लोग यहाँ पर दिल्ली-दिल्ली कहते हैं, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, मात्र पाँच से दस सालों के अंदर इन्हें उत्तर-पूर्वी भारत के लोग बता देंगे कि यह दिल्ली, जिनका शोषण करके दिल्ली के नेता और माफिया गठबंधन ने लगातार मुख्यमंत्री और कुर्सी पर बैठने का काम जिनका शोषण करके किया है, एक दिन वे इनसे सत्ता छीनेंगे और पूर्वी भारत के लोगों को इसी दिल्ली की कुर्सी पर बिठाने का काम करेंगी, यदि आप इन बातों को न सोचें, तो 60 प्रतिशत से अधिक लोग दस सालों के अंदर इस देश के दिल की राजधानी दिल्ली को हम मेहनतकश लोग आगे बढ़ाएंगें।

मैं दो-चार मुद्दों पर अपनी बात कहकर समाप्त कर दूँगा, क्योंकि आगे बजट है। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि सबसे अधिक पानी की परेशानी है। जो उत्तर-पूर्वी भारत के गरीब लोग हैं, वे यहाँ रेज़ आते हैं, यहाँ पर आकर मेहनत करते हैं, आपकी जिंदगी को बदलते हैं, जो पानी माफिया का यहाँ सबसे बड़ा तंत्र है तथा पानी और शौचालय से जो जुड़ा सवाल है, इस बजट में आप इन मुद्दों पर अत्यधिक फोकस करने का काम करें, यह मेरा आग्रह है।

मेरा दूसरा आग्रह है, श्रीमती शीला दीक्षित ने दुनिया में एक मिसाल दी, लोग कहते थे कि दिल्ली स्विज़रलैंड की ओर बढ़ रही है। मैं न आपके बजट की आलोचना कर रहा हूँ, चूंकि दिल्ली सबकी है, वित्त मंत्री जी आपका प्रयास दिल्ली को बनाने का है, आप सुंदर दिल्ली बनाना चाहते हैं, मैं यहाँ किसी विरोध के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि कांग्रेस की सरकार ने जो विश्व के तमाम देशों, अमेरिका, रूस, जापान, चाईना को अपनी ओर आकर्षित किया था, श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार ने जिस तरह से दिल्ली की गति को बढ़ाया था, आप उसी मजबूती से बढ़ाने का प्रयास करें। उत्तर-पूर्वी भारत के गरीबों को संरक्षित करने के लिए आपके बजट में कुछ नहीं है। उस बजट में उत्तर-पूर्वी भारत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, झुग्गी-झोपड़ी कॉलोनियों को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, दिल्ली को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यह देखने की जरूरत है। वहाँ जो उद्योग हैं, उसे पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली) : सम्माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। मैंने कभी जीवन में कल्पना नहीं की थी कि मैं इस सदन में खड़ा होकर बोलने की हैसियत रखूँगा। मैं किसान के परिवार का एक बच्चा हूँ, जो 28 साल की उम्र तक एक साइकिल के लिए तरसा है। हालाँकि, उसके बाद अपने लोक-संगीत के माध्यम से मैंने अच्छा जीवन भी देखा है। हम आर्टिस्ट, हम कलाकार स्वतः अपने घर से निकले हैं, उस समय जब इस देश को श्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जरूरत थी।

मैं इस समय उत्तर-पूर्व दिल्ली से सांसद हूं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय अरुण जेटली जी को जिन्होंने एक ऐसा बजट दिया है, जिससे हमारे विपक्ष के लोग इतने परेशान हैं कि उसे चुनावी बजट कह रहे हैं। मेरा मानना है कि इस विरोध के पीछे उनकी कुछ ऐसी बातें हैं, जिन पर बीजेपी अब कब्जा कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव का रहने वाला हूं। यूपीए के कारण ही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड के लोगों का लगातार पलायन हो रहा है। अब जब दिल्ली में एक ऐसा बजट आया है, जो बाहर से यहां आकर रहने वाले लोगों के लिए बहुत जवाबदेह और सुंदर बजट है, तब इसका विरोध मेरी समझ से बाहर है। जब दस साल या पंद्रह साल के बाद सरकार अचानक जाती है और एक नई सरकार एक अच्छी सोच के साथ आती है, तो कैसे उसका विरोध होता है, यह बात भी मेरी समझ से बाहर है। मेरे जैसे लोगों के लिए यह एक आश्चर्य की बात होती है। मैं कभी-कभी सोचता हूं कि इन घुमावदार भाषणों का अवसान होना चाहिए, जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, अब भगोड़ों के बोलने से नहीं भरमेगी जनता, बीजेपी की कोशिश है कि अब काम होना चाहिए।अब भगोड़े लोगों की साजिशों से नहीं भरमेगी ये जनता।...(व्यवधान) अभी तो पहला बजट है सभापति जी। अभी तो पहला बजट है ये, सांसें क्यों फूल रही हैं, जेटली जी के बजट का सम्मान होना चाहिए। ...(व्यवधान)

महोदय, मेरी दो-तीन ऐसी बातें हैं, जिन्हें मुझे लगता है कि आज के दिन बोल देना चाहिए क्योंकि दिल्ली से हमारे अन्य माननीय सदस्यों - उदितराज जी, प्रवेश जी, महेश जी, मीनाक्षी जी, सभी ने सारी बातें कह दी हैं। मेरी एक-दो नई बातें हैं, जिनको ध्यान में रखना चाहिए। झुग्गी-झोपड़ी के बीच शौचालय की व्यवस्था करने के लिए पिछले बजट में, वर्ष 2013-14 में मात्र 17 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी, उसके लिए इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, इससे पता चलता है कि उनकी सोच क्या है और किस तरह से नए ढंग से चलने के लिए हम तैयार हैं। जब चुनाव के समय हम लोगों के साथ गलियों में जाते थे, तो लोग जो बोलते थे, उसको मैं आग्रहपूर्वक वित्त मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगा क्योंकि जहां से मैं सांसद हूं, वहां पर खेल का मैदान नहीं है। एक भी स्टेडियम नहीं है, अगर उस पर आपका ध्यान जाएगा, तो उत्तर-पूर्व दिल्ली के लोगों को बहुत फायदा होगा। हमारे क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल भी नहीं है, जिसके लिए मैं आज यहां आदरणीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा क्योंकि लोग इसके लिए हमसे लगातार मांग करते रहे हैं। चूंकि मैं कलाकार हूं, गाना गाता हूं, मैंने हिन्दुस्तान के भोजपुरी लोक संगीत के लोकगायक के रूप में शुरूआत की। मैंने सिनेमा में भी काम किया है। पहले मुझे यह नहीं समझ में आता था कि यहां बैठा हुआ कोई सदस्य सदन को असत्य जानकारी देगा। अभी एक माननीय सदस्य, जिनका नाम सौगत राय है, ने मेरे लिए कहा कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं दिखता हूं। सभापति महोदय, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज हमें 16वीं लोक सभा में सांसद बने 75 दिन हो गए, जिनमें से 58 दिन अपने क्षेत्र में रहा हूं। अगर यह कम है, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। संसद में भी मैं मात्र तीन दिन नहीं रहा हूं। मैं चाहूंगा कि सौगत राय जी जवाब दें कि यह जानकारी उन्होंने सदन में कैसे दी, क्योंकि सारी दुनिया देख रही है और यह मेरे ऊपर पर्सनल अटैक है। मैं चुनौती देता हूं कि अगर 58 दिन की उपस्थिति के लिए मुझे गलत सिद्ध कर दिया गया, तो मैं आपकी हर बात सुनने को तैयार हूं। मुझे पता है कि यहां आकर बहुत से लोग अपने आपको बहुत भाग्यवान भी समझते हैं क्योंकि देश की सारी समस्याएं हैं।

सांसद कहीं का भी हो, जब हम किसी रास्ते से जाते हैं तो आए दिन लोगों से सम्पर्क में रहते हैं और उनकी समस्याएं और बातें सुनते हैं। कई ऐसी बातें हैं जो हम सदन में चर्चा करके सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, जिससे उन समस्याओं का अच्छा समाधान मिल सकता है।...(व्यवधान) मैं ज्यादा नहीं कहकर संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं करता। अगर मेरी बात किसी अन्य सांसद की मार्फत यहां कह दी जाए, तो वह भी मेरे लिए ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि - रोजी-रोटी दे दो, सड़क बनवा दो, बिजली का थोड़ा प्रबंध करवा दो, पानी बिना होंठ सूखे, नल चलवा दो और जेटली जी के इस बजट को समझो। इसे समझकर आगे प्रेम की गंगा बहा दो।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): The Delhi Budget in my opinion is a missed opportunity and a betrayal of the Delhi people.

The most important point is that our Constitution provides for a State Budget to be passed in this august House but is this a healthy practice? Is this a practice which any person who takes pride in Parliamentary democracy should accept? I stand before you and ask the Government why it has taken the Government such a long time to decide whether they want to form a Government or whether the Government would want the Delhi Assembly to be dissolved. It is an unhealthy practice which should not have been continued. A Government which has been in power for two months should have taken this decision at the first instance.

Secondly, I would like to ask from the Government, quoting from their own manifesto, to which they are still committed, saying day in and day out that BJP is committed to giving Statehood to Delhi. That has not been mentioned here.

The third point is that the BJP manifesto talked about decreasing the electricity rates by 30 per cent. If competitive populism is good in elections,

BJP should have continued with it. Why have they forgotten competitive populism after assuming power? Why have they not decreased the electricity tariff by 30 per cent? The AAP had done it in 48 hours. Why did the BJP forget this 30 per cent reduction promised in their manifesto?

When it comes to water, 1,100 mgd. is the demand but only 800 mgd. are being supplied. The Twelfth Five Year Plan says that 1,400 mgd. are required but there is no mention about it. How would you fulfil the water requirements when the Twelfth Plan says that 1,400 mgd. are required.

I would like to know from the Government whether for the development of Old Delhi is there sufficient amount of fund allocated. How will Old Delhi be developed? Let me give a classic example. Places like South Extension come in Unit A; places like Chandni Chowk and Jama Masjid come in Unit E. Why is that subsidy given to people living in Unit A areas? They do not require subsidy to be given. This has to be corrected by the Government.

The BJP manifesto talked about creating 50,000 jobs by making Delhi the new green capital of the world. Have you started any work on that? In your Budget, there is no mention about it. Your election manifesto talks about it but in your own Budget you have not even made a start to providing those 50,000 jobs.

I would like to bring to the kind attention of the Hon. Finance Minister and ask him why small traders and small shopkeepers in Delhi are being harassed day in and day out by VAT people. These are your own core constituency. Why is it that they are being harassed day in and day out? I was expecting the Finance Minister to increase the VAT exemption ciling from Rs. 50 lakh to Rs. 1 crore.

Delhi Police requires modernization and manpower. Neither in the Union Home Ministry's Budget nor in the Delhi Budget there is any mention about it.

Lastly, before concluding, I would have expected that the Budget would have talked about how to protect the heritage of Old Delhi but not a single mention is there about it. You have to protect the heritage of Old Delhi; unfortunately it is not there.

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री अरुण जेटली) : माननीय सभापति जी, मैं बहुत आभारी हूं कि बहुत बड़ी संख्या में इस सदन के सदस्यों ने दिल्ली बजट की चर्चा में भाग लिया है। यह प्रश्न उठा कि इस संसद को दिल्ली का बजट पारित करने की आवश्यकता क्यों है? स्वभाविक है कि यह एक संवैधानिक मजबूरी है। दिल्ली में विधान सभा है, दिल्ली यूनियन-टैरेटरी है और उसमें एक लैजिस्लेटिव बॉडी है और उसे दिल्ली बजट का अधिकार है। क्योंकि एक संवैधानिक परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि कुछ समय के लिए दिल्ली में सरकार बनी और वह सरकार ज्यादा नहीं चल पाई। इसलिए दिल्ली की विधान सभा एक सस्पेंशन की स्थिति में है और जब तक उस राजनैतिक परिस्थिति का, राजनैतिक प्रक्रिया के माध्यम से हल नहीं ा।मलता, जिसमें स्वभाविक रूप से दो ही परिस्थितियां हैं कि या तो यहां कोई लोकप्रिय सरकार बने, या फिर दिल्ली की ज्ानता के सामने वापस जाएं और उन्हें चुनाव की ऑप्शन मिले। जब तक उन परिस्थितियों का पड्हैसला नहीं होता, दिल्ली का बजट पारित करने का अधिकार केन्द्रीय संसद को है। इसलिए उस संवैधानिक आवश्यकता की वजह से हम यहां पर हैं।

दिल्ली के संबंध में बहुत कुछ कहा गया, दिल्ली का अपना एक चरित्र है। इस देश के सबसे पुराने शहरों में से दिल्ली एक शहर है। एक दिल्ली का देहात है जहां खेती अब न के बराबर है। उस देहात के क्षेत्र की अपनी विकास की और अपनी आर्थिक मजबूरियां भी हैं। जो मांग उठी कि लाल-डोरा एक्सपेंड हो, वह एक प्रकार से जिनकी जमीन चली गयी, उनके आर्थिक साधन का भी केन्द्र बन जाता है।

एक ऐतिहासिक दिल्ली है, जिसमें मॉन्युमेंट्स हैं, पुराना शहर है जो मुगलों के समय में बसा और उस ऐतिहासिक चरित्र की वजह से दिल्ली की एक पहचान भी बनी। 103 वर्ष पहले अंग्रेजों के जमाने में जब नई दिल्ली राजधानी यहां बनी, तो उसका अपने प्रकार का चरित्र बना और उसका निर्माण हुआ। उसके बाद तो एक प्रकार से होड़ लग गयी। एक समय में हरियाणा से लोग व्यापार के ा।लए दिल्ली आये। पश्चिम उत्तरप्रदेश और राजस्थान से आये। वर्ष 1947 में जब बंटवारा हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में लोग सीमा के उस पार से दिल्ली और उसके आस-पास बसे। उसके बाद जैसे-जैसे शहर का विस्तार हुआ, तो कोई भी देश का ऐसा प्रांत नहीं होगा जिसके लोग यहां न हों। चाहे पूर्वोत्तर के लोग हैं, जम्मू-कश्मीर के लोग हैं, दक्षिण भारत के लोग हैं, पूर्व के राज्यों के लोग हैं, जिसे एक कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर कहते हैं, जिसमें एक लघु भारत इस शहर में है। माननीय सैंगत राय जी बता रहे थे कि बहुत बड़ी संख्या में यहां बंगाली पॉपुलेशन है और शिक्षा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान है। दिल्ली के विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले लोगों में एक बहुत बड़ी संख्या में वहां के लोग जो दिल्ली में रहे, उनकी संख्या है। दिल्ली में क्योंकि आर्थिक गतिविधियां थीं, तो स्वभाविक है कि किसी काम की तलाश में लोग यहां ऐते थे। अब जिसे हम एनसीआर कहते हैं उसका भी विकास हो रहा है। दिल्ली के आस-पास के शहर जिन्हें हम पहले छेंटे शहर मानते थे, लेकिन आज वे पूरे विश्व में प्रभाव छेंड़ने वाले शहर बन गये हैं। गुड़गांवा शहर एक छेंटे शहर से आरम्भ होकर आज देश के सबसे आधुनिक शहरों में से एक बन गया है। नोएडा, ग्ा्ोटर-नोएडा, गाजियाबाद और अब फरीदाबाद की तरफ भी विस्तार हो रहा है। कुंडली, सोनीपत की तरफ विस्तार हो रहा है। माननीय दीपेन्द्र जी ने सही कहा कि एक हिस्सा बहादुरगढ़-रोहतक वाला बताया जहां दिल्ली के जो सबर्बन टाउन्स हैं उनके बसने की अच्छी गुंजाइश है।

सरकार की जो कल्पना सौ स्मार्ट सीटीज़ की है, कुछ नए होंगे तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनका छेंटे शहरों के आस-पास विस्तार होगा। आज अर्बनाइजेशन, सबर्बनाइजेशन एक तरह से नियम की तरह बन गया है और यह अपने आप में स्वाभाविक भी है। दिल्ली की दो तरह की तस्वीर है। एक दिल्ली ऐसी है, जिसे हम विश्व स्तरीय शहर बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ दूसरी दिल्ली ऐसी भी है, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया और जो एक चिंता का विषय भी है क्योंकि लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं। एक ही शहर में दोनों प्रकार के चरित्र सामने नज़र ऐंते हैं। दिल्ली के इस चरित्र को देखते हुए बजट के प्रावधानों को बनाया गया है। कई अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली के पास एक सहूलियत है कि दिल्ली में चूंकि इकोनोमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा है इस कारण सरकार को जो टैक्स ा।मलता है, उसकी संख्या अच्छी है। दिल्ली इस साल का बजट 36776 करोड़ रुपए का है। इन पैसों में से 31571 टैक्स तो दिल्ली से ही आ जाता है, जो दिल्ली शासन को ा।मलता है। कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू है, कुछ कैपिटल रिसीट्स हैं और केंद्रीय सरकार को इसमें 3672 करोड़ रुपये की ग्रांट ही देनी पड़ी है। 90 परसेंट पैसा दिल्ली के अपने साधनों में से ही दिल्ली के ा।लए आ जाता है। इस बजट में यह प्रावधान किया गया है कि जितने भी जन-जीवन को सुविधा देने के ा।लए साधनों में हम सुधार कर सकते हैं, वह हम लोग करें।

16.47 hrs.

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

दिल्ली की जो डेट जीडीपी रेशो है, वह अन्य राज्यों की तुलना में कम है 7.9 परसेंट के करीब है। अन्य राज्यों की ज्यादा होती है और इसके पीछे का कारण यह है कि दिल्ली में काफी टैक्स ा। मलता है और इसलिए सरकार को उधार लेने की कम आवश्यकता पड़ती है। दिल्ली शहर में अस्पतालों का एक नेटवर्क है। आज दिल्ली में पब्लिक हेल्थ केयर और प्राइवेट हेल्थ केयर दोनों की काफी सुविधा उपलब्ध है। 32 मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल, दिल्ली सरकार के 6 सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल हैं। उसमें 10 हजार बेड की सुविधा है। इस बार प्रयास है कि 1400 बेड और लगा दिये जाएं और दिल्ली में जो अस्पतालों की सुविधा है, उसका विस्तार किया जाए। दिल्ली में आने वाले वर्ष में एक नया मेडिकल कालेज रोहिणी के अंदर स्थापित किया जाए और वर्ष 2015 में वहां बच्चों को दाखिला मिलना आरम्भ हो जाएगा। जिसमें क्षेत्र देखे गए हैं उनमें एक क्षेत्र दक्षिण दिल्ली का पार्लियामेंटरी सीट है, जो दक्षिणी दिल्ली के देहात का क्षेत्र है, जहां से बिधूड़ी जी चुनकर ऐते हैं, वहां पूरे पार्लियामेंटरी क्षेत्र में कोई बड़ा मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल नहीं है, इसलिए वहां एक बड़ा मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल बनाने का प्रावधान है। दिल्ली में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से पचास डायलिसिस यूनिट्स और उपलब्ध हों, क्योंकि अभी 30 यूनिट्स उपलब्ध हैं। एक्सीडेंट और इमरजेंसी केसिस को देखने के ा।लए 110 एम्बुलेंस दिल्ली की सड़कों पर 24 घंटे उपलब्ध हों।

हेल्थ के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी, प्राइवेट, केंद्रीय विद्यालयों का काफी बड़ा नेटवर्क है। यह भी देखा जाता है कि महिला छैंत्राओं के ा।लए हर क्षेत्र में हाई स्कूल सरकार द्वारा चलाया गया लेकिन दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां ऐसा नहीं है और इस वर्ष उन दोनों क्षेत्रों में बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जमीन उपलब्ध करवाकर बीस नये स्कूल दिल्ली शासन की तरफ से इस बार बनाने का प्रयास

है क्योंकि दिल्ली में पूरे देश से लोग आकर बसते हैं, दिल्ली में अलग अलग प्रांतों और अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, इसलिए यहां हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की भी जानकारी हो। उर्दू, पंजाबी, संस्व्ृEत इन सब भाषाओं को बढ़ावा देने के ा।लए अकादमी हैं जिनको और मजबÃºत करना है और उनके टीचर्स को भी यहां पर उपलब्ध करवाने का एक प्रयास है।

प्रो. सैंगत राय (दमदम) : बंगालियों की भी एक अकादमी कर दीजिए।ह्न(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : दादा, आप चले गये। आप जब बाहर थे तो मैंने यह कहा कि बंगाली लोग तो हमें यहां आकर पढ़ाते हैं। वे हमारे विश्वविद्यालयों में सबसे ज्यादा हैं।ह्न(व्यवधान) एक नया स्कूल ऑफ प्लानिंग एाड आर्कीटैक्चर, आईपी यूनिवर्सिटी से एफीलिएट करवाकर बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो सामाजिक योजनाएं हैं, वे कई प्रकार की हैं जिनका बजट में प्रावधान किया गया है। खाद्यान्न सुरक्षा वाली भी हैं, उसके अलावा दिल्ली में Senior citizens between the age group 60 years and 69 years get Rs.1000, and above 70 years get Rs.1500 as pension. पिछले काफी समय से यह पेंशन रुकी हुई थी और इस बार इसकी संख्या भी बढ़ा दी गई है तथा 4 लाख 30 हजार लोगों को यह पेंशन दिल्ली के अंदर मिले, इसका प्रावधान किया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर सैक्शंस के ा।लए घर बनें, इसका प्रावधान बजट के अंदर किया गया है। नाइट शैल्टर्स की संख्या बढ़ाना, दिल्ली में पानी की सुविधा करना और पानी की सुविधा करने के ा।लए जो पानी के सोर्सेज हैं, मुनवको, हैदरपुर का जो पैरलेल चैनल है, उसको पक्का करना, रेणुका डैम का वहां पर निर्माण करना, जितनी अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं, जहां जहां संभव है, वहां पर पानी और सीवेज की सुविधा मुहैया कराना, इस बजट के तहत उसको पहुंचा पाना और दिल्ली में लगभग 500 एटीएम ड्रिंकिंग वॉटर के हों, दिल्ली में पीने का पानी जहां पर उपलब्ध हो, उसका भी प्रावधान करना।

इसी प्रकार सेनीटेशन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कई स्थानों पर बने हैं, उनका विस्तृत रूप से इसके अंदर प्रावधान किया गया है। यमुना नदी को भी साफ करने का इसके अंदर प्रावधान किया गया है।

ट्रांसपोर्ट के ा।लए मैट्रो एक्सपेंशन के अलावा 1380 लो फ्लोर बसेज और जितने भी स्लम क्लस्टर्स हैं, वहां पर 400 नयी क्लस्टर्स बसेज जो नागरिक वहां रहते हैं, उनकी सुविधा के ा।लए करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। बिजली के निर्माण और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक सुविधा हो जो पिछले कुछ महीनों में बिजली की जो समस्या दिल्ली में आई थी, बिजली अपने आप में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, लेकिन बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन का नैटवर्क था, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसमें इंवेस्टमेंट पिछले कुछ सालों में कम हुआ है, जिसकी वजह से वह कमज़ोर हो गया था और कई स्थानों पर कैूक अप करता था, उसको मजबÃºत भी करना है तथा दिल्ली में 84 फीसदी लोग वे होंगे कि जो प्रावधान केन्द्रीय बजट में किया गया है तथा जो बिजली के दर की कीमत बढ़ रही है, जिनको सरकारी सहायता के माध्यम से 84 फीसदी लोगों का बिजली का बिल जो पिछले महीने तक ऐता था, उससे कम किया जाएगा। इसके संबंध में माननीय सदस्य जिन्होंने इसमें भाग लिया है, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। बजट में बहुत विस्तृत रूप से सभी योजनाओं का इसमें जिक्र है। मैं उन सबमें नहीं जाता। मैं माननीय सदस्यों का बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया और मैं माननीय सदस्यों से यही दरख्वास्त करूंगा कि इस बजट को स्वीकृति देकर स्वीकार करें।

HON. CHAIRPERSON : I shall now put the Demands for Grants (National Capital Territory of Delhi) for 2014-2015 to the vote of the House.

The question is:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third Column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of the payment during the year ending on the 31st day of March, 2015, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 13."

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The Demands for Grants (National Capital Territory of Delhi) for 2014-2015 are passed.

-